Resolution re. need to take immediate steps for curbing flssiparous tendencies created in some Parts W the country

श्रीमति सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने यह संकल्प रखती हूं --

"Tbis House-expresses its deep concern at the flssiparous tendencies being created and encouraged in some parts of the country in; the name of religion, language and culture by certain sections;

ieels that these tendencies which are influenced by narrow sectional interests ignoring the larger national perspective, if allowed to grow unchecked, can harm the unity and integrity of the country; and therefore.

calls upon Government to ake immediate and effective steps for curbing these tendencies."

महोदय, बहुत सोचने समझने के बाद मैंने इस प्रस्ताव को आपके सामने रखा है। कुछ दिन पहले ही मेरठ में हुए सांप्रदायिक झगड़ों, में पंजाब के अकाली आन्दोलन पर काफी चर्चाएं हमारे सदन में हुई। विरोधी पक्ष ने इस चर्चा में सरकार की जितनी आलोचना करनी थी उतनी आलोचना की, परन्तु साथ ही साथ कांग्रेस (आई) की भी काफी निन्दा की। मैंने दो-तीन दिन यह चर्चा बड़े ध्यान से सुनी और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि अभी तक हम इन समस्याओं की गहराई में पहुंच नहीं पाये हैं। हमें इन समस्याओं की गहराई में पहुंचना अत्यन्त आवश्यक है। मुरादाबाद के झगड़े हों, चाहे जमशेदपुर के झगड़े हों या हैदराबाद के झगड़े हों, विरोधी दलों के सदस्यों ने अपना रोष प्रकट किया और कांग्रेस तथा सरकार को जितनी गाली देनी थी उतनी गालियां देकर वह चुप बैठ गये। जब इन झगड़ों की पुनरावृति होती है, तो फिर हम लोग, चाहे वह रूलिंग पार्टी हो, चाहे वह विरोधी पक्ष के लोग हों, हम सदन में बैठकर उस पर चर्चा करते हैं।

श्रीमान, आज देश में धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा और क्षेत्र को लेकर आपस में विद्वेष के वातावरण का निर्माण हुआ है। देश के कुछ भागों में समाज के कुछ अंगों में एक भय पैदा हो गया है और लोगों को जान-माल का खतरा भी महसूस होने लगा है। उनकी सुरक्षा पर कभी भी आघात हो सकता है, यह उनको महसूस होने लगा है, देश के एक कोने में हुई घटना पूरे देश और समाज पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है और ऐसा लगने लगता है कि सारा देश और समाज उन घटनाओं के चक्र में फैल गया है। एक आतंक का वातावरण फंस गया है। ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाती है। परन्तु ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए कौन दोषी है, आज हम इस सदन में बैठ कर इस पर विचार करें, यह अत्यन्त आवश्यक है।

श्रीमन् ऐसी भयंकर घटनायें जो राष्ट्र का विघटन करने में कुछ समय तक सफल दिखाई देती हैं, ये घटनाएं एक दिन में उत्पन्न नहीं होती। ये बहुत समय से प्री-प्लान्ड होती हैं और एक चिंगारी लगाने से विस्फोट का रूप धारण कर लेती है और समाज को जला देती हैं। इन घटनाओं के पीछे नेगेटिव फोर्सेज काम करती रहती हैं। विघटनकारी तत्व देश की एकता में बाधक हैं। इन तत्वों का मेन उद्देश्य है कि देश में अनारकी और कानून व्यवस्था को अशांत बनाने में लगे रहते हं ताकि प्रशासन पैरा-लाइज्ड हो और वह राजनीतिक शक्ति को पकड़ सके। इन स्वार्थी तत्वों का सांस्कृतिक उन्नति, धार्मिक आस्था या किसी जाति विशेष की सुरक्षा नहीं होती। यह केवल इनकी आड़ में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

श्रीमन्, हमें इन प्रश्नों को राजनीति से हट कर सोचना होगा। यदि हम इन प्रश्नों को राजनीति के साथ जोड़कर इस पर विचार करने की सोचते हैं तो इन प्रश्नों का हल शायद ही कभी निकल सकता है। यदि यह सदन और संसद, जो सारे देश के राज्य, क्षेत्र, भाषा, धर्म और संस्कृति का प्रति-

निधित्व करते हैं, इस मूल प्रश्न को सोचने और हल करने में असमर्थ हों तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि राष्ट्र की एकता और देश की अखंडता खतरे में है।

और यदि इसे समय पर नहीं सम्भाला गया तो देश छिन्न-भिन्न हो जाएगा और उससे स्थिति को सम्भालना कठिन ही नहीं होगा बल्कि असम्भव भी होगा। श्रीमान, साम्प्रदायिक झगड़े तो 1947 के बाद हमारे देश से खत्म होने चाहिए थे। यह दंगे ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवाद के हित के लिए दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया था और इतना ही नहीं और डिवाइड एन्ड रूल की नीति को अपनाया था परन्तु अब दंगे क्यों होते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। इसका उत्तरदायित्व किस पर है इसको हमें समझना होगा और विचार करना होगा। आज की युवा पीढ़ी को तो इस झगड़े के बारे में केवल स्कूलों और कालेजों में इतिहास की पुस्तकों से ही जानकारी मिलती थी ।

श्रीमन्, इस देश की संस्कृति महान है। यहां पर विभिन्न प्रकार की जातियां, धर्म, संस्कृतियां और भाषाओं के अनुयायी शान्ति और सहयोग से रहने के आदि हैं जब कभी विघटनकारी तत्वों ने इस शान्ति और सहयोग को छेड़ा तो समाज सुधारक, दार्शनिक नेताओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के लिए प्रचार किया। ऐसा हमें इतिहास से पता चलता है । परन्तु मुझे खेद है कि जब कभी इस प्रकार की शान्ति भंग होती है तो कोई समाज सुधारक और ऐसी संस्था हमारे सामने नहीं आती बल्कि हर घटना को राजनीतिक मोड़ दिया जाता है और राजनीतिक स्वार्थों को बढ़ावा दिया जाता है और बढ़ावा मिलता भी है। महात्मा गांधी जी ने 1919 में हिन्दू-मुस्लिम जनता को इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेने को कहा था वह प्रतिज्ञा यह है----

"With God as witness, we, Hindus and Muslims, declare:

that we shall behave towards one another as children of the same parents;

that we shall have no differences;

that the sorrow of each shall be the sorrow of the other; and

that each shall help the other in removing them

We shall respect each other's religion and religious feelings and shall not stand in the way of our respective religious practices;

We shall always refrain from, violence to each other in the name of religion."

श्रीमन् महात्मा गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस दल ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से कोशिश की और इसी कारण हिन्दू-मुस्लिम ने कन्धे से कन्धा मिला कर स्वंत्रता संग्राम में एकजुट हो कर काम किया और इस देश को आजादी दिलाने में कामयाब हुए ।

श्रीमान, मेरठ में हुए झगड़ों पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री इन्द्रदीप सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा। माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रसाद माथुर जी ने इसको गाली समझा परन्तु मैं माथुर साहब से कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो हिन्दुओं की एक सांस्कृतिक संस्था कहती है और जिसका भारतीय जनता पार्टी से सीधा संबंध है क्या उस संस्था का यह कर्तव्य नहीं है कि वह समाज में विशेषकर अल्पसंख्यकों में एक विश्वास पैदा करे परन्तु ऐसा होता नहीं है। जब भी ऐसा कहीं झगड़ा होता है, फसाद होता है, दंगा होता है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम किसी न किसी रूप में अवश्य आता है . . .

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार): आता नहीं फंसा दिया जाता है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम जोड़ दिया जाता है (व्यवधान)

श्रीमती सरोज खापर्डे: यह आप जानते हैं। (व्यवधान)

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : आप भी जानती हैं ।

श्रीमती सरोज खापर्डे: मैं भी कह रही हूं आप जानते हैं । आप इंट्रप्ट मत करिए। आपको जो भी कहना हो जब आप अपने विचारों से अवगत कराएंगे तो मैं बड़े ध्यान से सुनूंगी ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोल रही हैं।

We are listening to her. Why are you worried?

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: Thank you very much, Mr. Kulkarni.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI; This is the first time we are hearing your serious lecture. This is not intervention.

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: Thank you. very much; at least you should hear patiently.

SHRI 3RVIND GANESH KULKARNI; Yes, we are listening to your welLformed views.

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: And I hope you would not interrupt me.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI; At least you should thank .me.

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: Yes, I am thanking you.

इसके लिए मैं माथुर जी से स्वयं विचार करने के लिए कहूंगी। परन्तु मैं यह अवश्य उनसे कहना चाहूंगी कि हिन्दुओं की संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जो ऐसा कहते हैं उस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यह कर्तव्य हो जाता है कि माइनारिटीज को सुरक्षा ही नहीं बल्कि विश्वास भी दिलाएं।

श्रीमन्, साम्प्रदायिकता एक बहुत बड़ा विष है जो हमारे सामाजिक जीवन में प्रवेश कर चुका है और साम्प्रदायिक झगड़ों में अधिकतम बेगुनाह ही मारे जाते हैं। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जून 1968 में श्रीनगर में हुई नेशनल इन्टीग्रेशन की कान्फ्रेंस को एडरेस करते हुए, सम्बोधित करते हुए कहा था कि:

"The great menace which our country faces today is that of communalism. The second menace is that oi provincialism or regionalism or parochialism. In fact, it is an extension of the same sort of feeling. The need for naitional integration therefore does not arise merely from a moral purpose in the world. As it exists today, as it is evolved today, national integration is the very condition of our national survival. It is the essential necessity if we are to go forward with our developmental planning and to progress in unity and strength. Our people must be made to understand the virus of communalism and of regionalism which seems to corrode our national will and purpose."

श्रीमन्, समाज से साम्प्रदायिकता को जड़ मूल से हटाने के लिए सारे राजनीतिक दलों को एक होकर काम करना अत्यन्त आवश्यक है और सदन में और सदन से बाहर सरकारी आलोचना को छोड़कर, सरकार को पूरा सहयोग देना होगा। इतना ही नहीं इसके साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा। जैसे 6 अक्टूबर को हमारे माननीय सदस्य श्री बी. एन. तिवारी–मुझे लगता है कि वे सदन में नहीं हैं इस वक्त–ने कहा था कि "आर्य समाज जो पहले कभी समाज सुधारक संस्था थी, उसने हिन्दू और सिक्खों के बीच में एक खाई पैदा कर दी है। अब रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं को इस कार्य को एक पर्व लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए।"

श्रीमन्, आज निजी स्वार्थों के लिए समाज में ऐसे तत्व और ऐसी उग्र शक्तियां पैदा हो गयी हैं जो देश के लिए अत्यंत घातक साबित हुई हैं। ये स्वार्थ, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री खुशवंत सिंह जी ने 16 सेप्टेम्बर को 'हिंदुस्तान टाईम्स' के अपने एक लेख में लिखा है What do the Sikhs want? Akali demand."

इस लेख में उन्होंने कहा है कि श्री जगजीत सिंह चव्हाण जो खालिस्तान की मांग के संस्थापक माने जाते हैं उन्होंने इंग्लैंड में ट्रेवल एजेंसी खोली हुई है, जिसकी सारी क्लायेंटेल, सिक्ख इमिग्रांट्स हैं। जब इन सिक्ख भाईयों को वीसा या वर्क परमिट नहीं मिला तो चव्हाण ने उनको मजबूर किया कि वे खालिस्तान के आन्दोलन के सताये हुए समर्थक अपने को घोषित करें। और पॉलिटिकल एसाइलम की मांग

करें। वह अकाली मंत्रीमंडल में मंत्री भी रह चुके थे। इस प्रकार का निजी स्वार्थ हर घटना के पीछे है, चाहे वह स्थानीय हो या राष्ट्रीय। ऐसे तत्वों को जड़मूल से निकालना होगा। इस का उत्तरदायित्व केवल सरकार पर नहीं बल्कि सारे राजनैतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं और सारी जनता पर है। यदि इन तत्वों को किसी कारणवश किसी और से भी बढ़ावा दिया गया तो यह तत्व देश की एकता, राजनैतिक और सामाजिक सहिष्णुता के लिए नासूर साबित होंगे और कुछ समय के बाद ऐसे स्वार्थों को प्रोत्साहन देने वाली शक्तियों को अपनी गलती का एहसास होगा।

श्रीमन, धर्म या जाति को ले कर जो उपद्रव किए जाते हैं वे प्रीप्लान्ड होते हैं और 99 परसेंट जनता का इन उपद्रवों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यदि उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाये तो पता लगेगा कि आम जनता इन दंगों के पीछे नहीं है बल्कि कुछ विघटनकारी तत्वों के कारण समाज में, देश में, शहरों में और गांवों में ऐसे दंगे होते हैं और इन दंगों में हमारी बेगुनाह जनता मारी जाती है। गृह मंत्रालय की 1981-82 की रिपोर्ट में साम्प्रदायिक दंगों के आंकड़े आप को देना चाहूंगी।

Number of communal incidents—319 Number of persons killed—196 Number of persons injured—2,613

श्रीमन्, इन दंगों से राजनैतिक तथा उग्रवादी शक्तियों का कितना हित हुआ, यह हम नहीं जानते, परन्तु इन दंगों का होना हमारे समाज पर एक कलंक है, इतना मैं कह सकती हूं।

पूजा के स्थान को लेकर झगड़े होते हैं। पूजा के स्थान को लेकर झगड़े होते हुए हम ने कभी नहीं देखे, लेकिन पूजा के स्थान को ले कर भी झगड़े हो रहे हैं। मेरठ का हाल देखिए। मैं मेरठ का उदाहरण देना चाहूंगी। मेरठ में पूजा के स्थान को लेकर झगड़ा हुआ। उसी प्रकार अभी-अभी बंगलौर में पूजा के स्थान को लेकर झगड़े हुए जिन में 5 हजार से अधिक लोगों ने आन्दोलन किया। इन में एक व्यक्ति की जान गई। आए दिन ये साम्प्रदायिक झगड़े एक सम्मानित राष्ट्र और सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देते। धर्म की आड़ में ये दंगे लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।

श्रीमन्, भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बनाया गया और 1966 में हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को पंजाब से अलग किया गया। हमारी माननीय सदस्या डा. राजिन्द्र कौर--आज वह भी सदन में नहीं हैं, होती तो शायद कुछ जवाब उन से भी मिलता -- डा. राजिन्दर कौर का कहना है कि लोकसभा में अकाली दल के सदस्यों ने इस प्रकार के पंजाबी सूबा को अस्वीकार किया था। फिर भी पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बना और आशा थी कि अकाली दल संतुष्ट होगा। परन्तु अब पंजाब में सिखों के लिए एक पृथक राष्ट्र के नाम पर खालिस्तान की मांग की जा रही है। सिख भाइयों को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए कहने के लिए विदेश के सिख भाई खालिस्तान की मांग को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उन्होंने सिखों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सह-सदस्य बनाने की मांग भी की है। अक्तूबर 1973 में आनन्दपुर साहब का जो प्रस्ताव पास किया गया शिरोमणि अकाली दल के एक कन्वेंशन ने उसे खालिस्तान सा रूप दिया। शिरोमणि अकाली दल और गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने सिख संस्कृति के लिए जो मांगें रखी हैं उन को कुछ सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। उन को कुछ सीमा तक माना जा सकता है जैसे ट्रेन का नाम रखा जाय हरविन्दर एक्सप्रेस, या अमृतसर नगर को पवित्र नगर घोषित किया जाये, इत्यादि। शिरोमणी अकाली दल ने भाषा के नाम पर पंजाबी सूबा लिया और भाषा के नाम पर ही हरियाणा, हिमाचल और रजस्थान के क्षत्रों पर उन की नजर है। राजनीति के नाम पर चंडी गढ़ और भाखड़ा पर नियंत्रण और सतलुज, रावी और ब्यास के पानी के बंटवारा वह चाहते हैं लेकिन श्रीमन्, इन सवालों को ले कर इतना बड़ा मोर्चा लगाने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे विवाद तो दूसरे राज्यों के सामने भी हैं परन्तु यह अकाली मोर्चा तो किन्हीं और निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगाया जा रहा है और वह

[श्रीमति सरोज खापर्डे]

है खालस्तान । कहा जाता है कि सिख संस्कृति और सिख धर्म खतरे में है । हमारे माननीय सदस्य श्री खुशवन्त सिंह जी ने 6 अक्टूबर को इसी सदन में कहा था कि खालिस्तान की मांग को विदआउट ऐनी कंप्रोमाइज रिजेक्ट किया जाए । फिर इस मांग के अतिरिक्त और मांगों के लिए मोर्चे की क्या आवश्यकता है इसी महीने के अंत तक 25 हजार से बढ़ कर 50 हजार लोग जेल में जाएंगे यह क्या है और इसके साथ ही श्री खुशवन्त सिंह जी ने चंडीगढ़ पर जो हमारी प्रधान मंत्री जी का निर्णय है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसी सदन में कहा कि:

Prime Ministers arbitration in whch Chandigarh was granted to Punjab provided that Abohor and Fazilka were handed over to Haryana, I think, was an act of a politician and not an act of a far sighted statesman."

मुझे श्री खुशवनत सिंह जी से कुछ कहना था। वह स्वयं एक उच्च कोटि के बुद्धिजीवी है । उनसे इस प्रकार के विचारों की हम ने कभी आशा नहीं की थी। यदि सिख संस्कृति भाषा और राजनीति के कारण उन की सारी मांगों को स्वीकार किया जाये तो उस की दूसरे राज्यों में क्या प्रतिक्रिया होगी इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते है। पंजाब में राजनीति और धर्म शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति में कोई अंतर नहीं मानता । शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति जिसको गुरूद्वारों का प्रबंध सौंपा गया है उसको राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए । राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के शब्दों में मैं बताना चाहती हूं कि उन्होंने कहा था "कि सिख सिद्धान्त और परम्परा के अनुसार गुरूद्वारे उपासना, सेवा और सत्संग के स्थान है । शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी का सिखों का अलग राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव धर्म और उपासना के विरूद्ध है। यदि एक अलग धार्मिक समुदाय को एक अलग राष्ट्र मान लिया जाय तो इसका मतलब होगा कि सिख एक राष्ट्र से बढ़ कर है क्योंकि वह सिर्फ पंजाब में नहीं रहते और फिर भारत के ही नागरिक नहीं है बल्कि दुनियां के कई अन्य देशों में बसे हुए है। अमेरिका के एक सिख नागरिक को अगर अमरिकी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसे अन्य जो भी नाम दिया जायगा वह हास्यास्पद होगा । सिखों के लिये एक अलग राष्ट्र या खालिस्तान की मांग करना देश की एकता को चुनौती है और सिख धर्म और गुरूओं के महान कार्य पर चोट है ।"

श्रीमन्, आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव 1973 में आया । 1977 में केन्द्र में जनता सरकार जिस में अकाली दल भी शामिल था और पंजाब में अकाली दल का मंत्रिमंडल बना परन्तु यह सब मांगें जिस उग्र रूप में इस समय सामने आयीं, जनता मंत्रिमंडल के सामने नहीं आयी थी, उनके सामने यह सारी चीजें इतने उग्र रूप में नहीं आयी थी । इससे विश्वास होता है कि शिरोमणि

3 P. M.

अकाली दल जो चुनाव में हार गया, अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण यह आन्दोलन चला रहा है । इसके क्या दुष्परिणाम होंगे या हो चुके है या होने वाले है, इस की चर्चा इसी सदन में अक्टूबर 6 को हो चुकी है । मेरी केन्द्रिय सरकार और प्रधान मंत्री से अपील है कि वह खुले दिल से अकालियों से बातचीत अवश्य करे, परन्तु निर्णय लेने से पहले उसकी दूसरे राज्यों में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका भी ध्यान रखें ।

श्रीमन्, मैं आपके सामने जिक्र करना चाहती हूं कि कुछ समय पहले कन्नड़ भाषा को लेकर कर्नाटक में कुछ नगरों में हिंसात्मक उपद्रव हुए । 6 दिन तक जत्थे शहरों में जाते रहे और उस जत्थे में कन्नड़ फिल्म स्टार्स भी शामिल हुए थे । इधर सन आफ दि आयल सिद्धान्त का विष समाज में प्रवेश कर चुका है । संकीर्ण प्रवृति समाज और देश को बहुत क्षति पंहुचा रही है । इस प्रवृति का दमन राष्ट्रहित के लिए करना अत्यंत आवश्यक है। (समय की घंटी)

श्रीमन्, मैं अधिक समय नहीं लूंगी । दो तीन मिनट का समय आप मुझे देंगे, ऐसी उम्मीद करती हूं।

श्रीमन्, अभी प्रेस बिल के बारे में बिहार में रैलियां आयोजित की गई। संसद में भी विरोधी दलों ने इस बिल की काफी आलोचना की । मैं इस बिल के मैरिट्स और डिमैरिट्स में जाना चाहती हूं परन्तु यह सदन को जरूर बताना चाहूंगी कि हिन्दुस्तान में समाचार पत्र बढ़ा-चढ़ाकर ऐसे समाचारों को छापते हैं जिससे लोगों के मन में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि समाचार-पत्र न हों तो कोई आंदोलन भी नहीं होगा। मैं उर्दू तो नहीं जानती हूं, परन्तु मुझे बताया गया है कि इस मोर्चे को बनाने में कई उर्दू समाचार पत्रों का भी काफी हाथ है।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । जो देश अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के कारण, विभिन्नता में एकता के कारण प्रसिद्ध है वह अब राष्ट्र-विरोधी, विघ्नकारी तत्वों के कारण उस एकता को बनाये रखने में असमर्थ दिखाई पड़ता है । हमने संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया है । हमारा संविधान फैडरल है, फिर यह आटोनामी को लेकर जो आन्दोलन और मोर्चे लगाये जाते हैं वह हमारी संसदीय प्रणाली में कहां तक उचित है यह मेरी समझ में नहीं आता । प्रजातंत्र में जहां विचारों की स्वतंत्रता है वहां कुछ जिम्मेदारियां भी हम पर हैं । हमारे विरोधी राजनीतिक दलों को जब चुनाव द्वारा विधिवत राज्य सत्ता नहीं मिल पाती है तो वह इस प्रकार के आन्दोलनों में लग जाते हैं । इससे राष्ट्र और समाज का हित नहीं हो पाता । वह यदि शासन का भय न हो तो शासन चल नहीं सकता है । क्षेत्रीय, भाषायी, सांप्रदायिक विविधताओं का इस विशाल देश में होना भी स्वाभाविक है । तनाव भी हो सकता है, तनाव आर्थिक कारणों से भी हो सकता है परन्तु यह तनाव हिंसात्मक उपद्रव का रूप न लेकर लोकतांत्रिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। संघीय, फैडरल सैटअप में आतंक और उपद्रव की कोई गुंजाइश नहीं होती । वे संकीर्ण तथा स्वार्थ भाव से प्रेरित होते हैं । रास्ता रोको, नहर रोको, जेल भरो, उत्पादन रोको के पीछे जो प्रदर्शन, जलूस और बन्द आयोजित किये जाते हैं उनके पीछे क्षेत्रीयवाद और निहित राजनीतिक चाल होती है । अब तो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसे बन्द होने लगे हैं । आज ही के अखबार में जैसा मैंने पढ़ा, हिन्दुस्तान टाइम्स में 'तमिल नाडु इज आल सैट फार बन्द' छपा है । तो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी बन्द और धरना आयोजित किये जा रहे हैं । तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य भर में कावेरी जल को लेकर बन्द का आयोजन करना और कृषि भवन के सामने वैस्ट बंगाल के मंत्रियों तथा वामपंथी संसद सदस्यों और एम. एल. एज. का धरना लगाना इसके उदाहरण हैं।

यह सब राजनीतिक चालें हैं । श्रीमन् जब हमने फेडरल सैट-अप को स्वीकार किया है तो इस प्रदर्शनी की क्या आवश्यकता है। यह सब राजनीतिक तरीके की अपनी चालें हैं । हमें इन मामलों को लेकर संसद् में गहराई से सोचना होगा कि यह सब कुछ देश की एकता और स्थायित्व को कहां तक खतरा पंहुचा सकते हैं । इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार को मजबूती से काम लेना होगा। जहां बातचीत करने की आवश्यकता है, करनी चाहिए परंतु किसी क्षेत्रीय या राजनीतिक दबाव में कोई निर्णय नहीं लेना होगा जो देश की इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को बाद में खतरा पैदा हो ।

श्रीमन्, देश के सामने विषम समस्याएं हैं यदि हम आए दिन की घटनाओं में लगे रहें तो इस समय विकास का काम जो जोरों पर है पीछे पड़ जायेगा। यदि विघटनकारी और पृथकता को बल देने वाली शक्तियों का दमन करने में कानून और प्रशासन प्रणाली पर्याप्त नहीं है उसको भी बदला जा सकता है । इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जो भी राजनीतिक दल या कोई भी दूसरी संस्था बढ़ावा देती है उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी जो संस्था ऐसी प्रवृत्तियों को भड़काने वाले पोस्टर निकालते हों उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी।

श्रीमन्, मैं इस सदन द्वारा अपनी समस्त जनता से आग्रह करना चाहूंगी यदि देश की एकता, स्थिरता और अखंडता

[श्रीमति सरोज खापर्डे]

को यदि इन इने गिने स्वार्थी तत्वों से धक्का लगा या खतरा पैदा हुआ तो आज की संतति और आने वाली संतति कहेगी कि हम भगवान महावीर, भगवान गौतम-बुद्ध, गुरू नानक देव जी और गांधी जी के स्वपनों के भारत को जिसको पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, पं. पंत जैसे नेताओं ने बड़े परिश्रम और बलिदान से राष्ट्र का निर्माण किया है उसको हम बचा नहीं पाये । यह सबको विदित है कि भारत ने विश्व को शांति और पंचशील सिद्धांत दिये परन्तु कुछ संकीर्ण तत्वों के कारण उस शांति को और उन आदेशों को अपने ही देश में और समाज में स्थापित करना कठिन हो रहा है । श्रीमन्, 1956 में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ । यह पुनर्गठन राज्यों की भाषा और वहां की संस्कृति को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था । परन्तु आज हम देखते हैं कि संस्कृति और भाषा के आधार पर भी अशांति फैलायी जाती है । कुछ उग्र शक्तियां भी जैसे नक्सलाइट्स अपना सिर उठा रहे हैं और देश के कुछ भागों में आंतक फैला रखा है ।

श्रीमन् हमारा प्रजातंत्र विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है । स्वतन्त्रता प्रजातंत्र की जान है । हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह इसमें स्वच्छंद हो और देश के हित के विरुद्ध काम करें । जैसा मैंने पहले कहा है कि देश के सामने देश निर्माण का बहुत बड़ा कार्य सामने है । यह इतना महान कार्य देश की प्रधान मंत्री हमारी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हो रहा है । प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा निर्धनता को दूर करना है और शोषित लोगों की दशा को सुधारना है और देश की आर्थिक स्थिति को उन्नत करना है परन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब सारे राजनैतिक दल, समाज और जन्ता अपने पारस्परिक और तंग दृष्टिकोण को दूर करके राष्ट्र निर्माण और विकास में लग जाये ।

हम सब को पता है कि हमारे कुछ छुपे हुए शत्रु हैं जो देशी या विदेशी हो सकते हैं जो हमारी उन्नति को देख नहीं सकते । हमारे द्वार पर शत्रु मुंह खोले बैठे हैं और हमारी जरा-सी कमजोरी से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं । कुछ विदेशी सरकारें भी उनको हथियारों से लैस कर रही हैं । इस सारी वस्तु स्थिति को हमें एक मत से देखना है । हमारे राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं जो एक प्रजातांत्रिक और संसदीय प्रणाली में स्वाभाविक हैं । परन्तु यह मदभेद हमारी एकता और एकीकरण को नहीं छूना चाहिए । हमें अपनी स्वतंत्रता जो हमें बड़े बलिदान के परिणामस्वरूप मिली है, को सुरक्षित रखने के लिए हमें एकमत होना होगा अपने संविधान और संसदीय प्रणाली को जो विवेकशील व्यक्ति हैं और जो राजनैतिक दल हैं उनको इस विषय पर चिन्तित होना चाहिए । यदि देश की एकता गई और उग्र शक्तियां विघटनकारी तत्व और स्वार्थी लोगों को पूरी शक्ति से नहीं रोका गया तो यह संसद्, यह संविधान और भारत की बहुत बड़ी क्षति होगी जिसका उत्तरदायित्व हम सब पर होगा । यह एक प्रत्यक्ष चेतावनी है और देश को इन शक्तियों से बचाने के लिए सशक्त कारण हैं । हमारी सरकार राजनैतिक दल और जनता को इस चेतावनी को कार्य रूप में परिणित करना है । नान-एलायन्स कान्फ्रेंस के समय भी ये शक्तियां सरकार को मैलाइन करने का प्रयास करेंगी । इसलिए इस वक्त हर तरफ से चौकसी की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, आपने मुझे जो ज्यादा समय दिया है उसके लिये मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं । विरोधी दलों से भी मैं अपेक्षा करूंगी कि वे भी इस पर थोड़ा सोच-समझ कर अपने विचार व्यक्त करें और इस विषय पर सरकार के साथ सहयोग करें और ऐसी प्रवृत्तियों को दूर भगाने की कोशिश करें, ऐसी प्रवृत्तियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने में सहयोग दें जो हमारे देश के लिए घातक हो सकती हैं और जो देश को अलग-अलग टुकड़ों में बांटना चाहती हैं ।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN); Now before the other speakers speak, I would like to share with you some facts. The time is already 3.10,. or littie more than that. We have exactly 110 minutes left with us. There are fourteen persons who have given their names and aU of them are present. So even if I give five minutes to each Member, it comes to 70 minutes. The Minister will take 15—20 minutes. And the Mover of the Resolution will also have to reply and will take 10 minutes. So it is oracti-cally impossible to finish the Resolution. According to the rules, this Resolution will go to the week after when it will continue. But the week after happens to be the 29th, and on that day the Rajya Sabha is not sitting. There-fore, the Resolution will lapse. So what I would request is that the hon. Members may decide now. The Resolution is going *to* lapse if each one of you will take time, or lesser number o-f people will be covered. If you want the Resolution to be completed today and passed by the House, you will have to bear with me because x can hardly give flve minutes for each Member. I would like to be guided by the House, and not be put to any difficulty.

श्री सरज प्रसाद (बिहार) : आप समय बढ़ा दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर. रामकृष्णन्) : इस पर 14 आदमी बोलने वाले हैं और वे सभी यहां पर बैठे हुए हैं ।

उद्योग मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : आप थोड़ा-थोड़ा समय दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर. रामकृष्णन्) : 5 बजे तो हाफ एन आवर डिसकशन है ।

I will give 15 minutes for each speaker and the Resolution will lapse.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): You have given the judgment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): I am guided by the House.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO; We will not like the Resolution to lapse. Let us aU co-operate with you,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R RAMAKRISHNAN.): It is not possible. I have given you the arthomatic of the whole thing.

SHRi H. HANUMANTHAPPA (Kar-nataka): It is such an important Resolution. We should see that it Ls passed and should not allow it to be lapsed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): We have to give-only five minutes to each Member. Hon Members, why I took you into confidence is that two plus two make. four. If 14 Members have to soeak and the Minister the Mover of ihe Re-solution have to speak, it definitely means that each person will not get more than five minutes. If you do not sit down at the end of the five minutes. I will call the next speaker. I will have to be merciless. I do not want to get your wrath later, your accusation that the Vice-Chairman is suing his power. So, I took you into confidence. So, if you want the Resolution to be passed you will have to stick to time.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam) : I do not think that a Member can express his views on the Resolution within five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R RAMAKRISHNAN): You are divided in your opinions. Tell me what I should do

SHRi DINESH GOSWAMI: I thi passing oi the Resolution would not change the situation. The Members shoula be given reasonable time so that they can express their views, so that the Minister and the Government may be guided by their views.. After all passing of the Resolution will not strengthen the hands of the Government. Though I will not be able to-

[Shri Dinesh Goswami]

speak, I submit you give ten minutes each for the Members who wili speak. We should not insist on passing of the Resolution.

SHRI ARABINDA GHOSH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, sir, 1 shall deal with this Resolution trom another context. The Resolution expresses deep concern at the flssiparous tendencies an^ so on. Why these flssiparous tendencies and in the name of religion, language and culture by certain sections? What is the background? Only some Resolution and some emotional speech will not solve the problems of the country. During the last 34 or 35 years of independence what is our experience?

We know this society is a class-dividea society. Here the concentration of wealth is in a few hands. Here the exploitation of man by man continues. Still the problem of the bonded labour has not be solved. Still the Harijans are suppressed. The landless labourers have got no land to till- They are in debts. They have been starving. All the produce of the farmers and the agricultural labourers and the poor peasantry is concentrated in the hands of jotedars and Zamindars. There js exploitation havey exploitation, even after 35 years of independence. We find that there is the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. But what we find is that the monopoly houses are reaping the maximum fruit •out of the toils of the labour and the toiling masses. Even we see from the facts supplied by the Government and sqmi-Government institutions that the profits of the Tatas and the Birlas every year amount Rs. 100 crores. There is no ceiling on profits. The un-employment continues like anything. There are more than three crores unemployed on the registers, and so many crores of under-employed and half-employed. There are crores of people in the rural areas who work for two or three months a year. The industrial production has increased, bu*. there is no market. People hava no purchasing power. The Government is advocating that the people below the poverty-line have decreased. But that is on paper, that is in words only. In practice the people living beiow the poverty-line getting Rs. 20/- per month are increasing more and more.

Agricultural production appears to have completely flopped. We have to buy millions oi tonnes of wheat from the USA. The cost is Rs. 400 crores. This morning my question was there on this subject. So rrtich money is being spent in foreign exchange. There is no proper procurement by the Food Corporation of India. It is a commercial' concern. People call it the Food Corruption of India. There is total failure. There is no buffer stock. We have still to depend on rains. There is total failure on the irrigation front if you take fhe per capita figures. There are no irrigation water-ways. Actually there is no scientific planning. Yesterday to a question put by our colleague, Mr. Nirmal Chatterjee, the Railway Minister said that though the foundation was laid, no money was allocated ior the railway project from Howrah to Amta in West Bengal. This is defective planning. No perspective is there.

The deficit in balance of payments stands at about Rs. 6,000 crores, though exports have increased. Layoffs and lock-out are increasing in major industries and workers are not responsible for it. There is managerial corruption. There is no proper management to tackle the problems of the workers. There is no proper planning to tackle the problems of production. Everything is in a mess. So every we are seeing in the country one lock-out after another and thousands and Iakhs of workers becoming newly unemployed. The Bombay textile strike is perhaps the longest strike in the world. Why this strike? The *Statesman* dated 16-9-82 started clearly that the total losses, in terms of exports, workers' salaries and wages, establishment, everything, come to Rs. 1,430 crores. Who is responsible for this? Are the workers responsible? Are the employers responsible? Is the management responsible? Or is

it the policy of the Government that is responsible? We raised many questions in the Commerce Ministry's Consultative Committee. The textile strike was discussed here. But there is no solution. People are groaning. Who is responsible? The entire policy of the Government is responsible. This should be changed,

I have pointed out that the IMF loan of Rs. 5.000 crores will not help us in having an independent economy. The IMF could not force us to take this loan. Have they forced us? We cur-selves went in for it with all the conditionalities that were attached to it. And now our country is suffering. The maladies and the crises instituted by the ruling party have brought this attack on culture and communal riots and flssiparous tendencies everywhere in the country. The Government seems to have no control over the situation. There is no law and orler. They talk of cooperation, but they do not pay heed to our concrete and cons-trucive suggestions for developing an independent economy. They do not listen to us. But if we look at West Bengal, many lapses may be there, many other things may be there, but there are n0 flssiparous tendencies, there is no attack on culture and there are no cc-mmunal riots. Why? if a sustained effort is there, if proper planning is there, if a proper perspective is there, then certain things can be checked by the Government of India. Now this resolution moved by the hoi-Member after 35 years of independence has a background. And who is responsible for this background?

So our suggestion is that immediate scientific planning is necessary. Our Sixth Plan is in doldrums. No target is fulfilled. Even the 20-point programme, if we discuss in the House, will prove that 50 per cent of tha targets are not fulfilled. For example, bonded labour, poor peasantry, which create the wealth of the country, er deprived of their due share in our national economy. This is the efl'ect of the continous anti-working class policy, anti-planning policy, of the Government of India. It is high time we recognised aU these maladies, these defects, and corrected them with the help of the Opposition.

Another thing which has provoked the people is the ISMA, the MISA, etc. What is the necessity of these black Acts? To suppress the working people who are the assets of the country. When the Minister replied to the questions yesterday, he was all sympathy for the workers. But is that sympathy to bring in ISMA, to bring in MISA, to bring in Hospital Amendment Act, etc. to suppress the workers? Minus the workers, minus the labour, the capital cannot exist. Capital means capital labour, land labour, capital or-ganisation. These are the four pillars of our national economy. Somebody was saying that Bombay mills will be closed. Are the employers able to run the mills without the labour? Therefore, a proper planning is necessary, otherwise, the resolution moved by the honourable Member will only be a flop, the document will only remain a document, nothing more. With these, words I conclude. Thank you.

SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL (Maharasthra): Mr. Vice-Chairman, I am speaking for the flrst time in the House on the subject regarding the flssiparous tendencies, that is, the communal tendencies, which are being created and encouraged especially in the name of religion, in culture, by certain sections which are harmful to the unity and integrity of our nation. Therefore, it is. my request or demand that the Government should take immediate and e.' tive steps for curbing these tendencies. I shall firstly put some examples of incidents of communal riots where I visited I saw and I tried to pacify them, which have arisen out of their rotten religion, rotten culture and, *to* some extent, rotten educational system also. With this I shall also suggest some remedies. It is said that India has unity in diversity. And this is also a fact that because of the strong leadership of our Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, India is reeog-

[Shri Dinkarrao Govindrao Patil] nised as one o* the good democratic nations in the world which has an ideal unity and integrity. But some communal forces, based on such religions, are trying to destroy the unity ane integrity of our nation. Though the principles of all the religions are one and the same, these reactionary forces make the wrong interpretation of these religious principles to exploit tlie people of our nation. In India there are Hindus, Muslims, Jains, Buddhists and Christians. These are the main religions. We have got from experience how some rotten religion is a posion to illiterate, poor and innocent persons in our country.

Therefore, I shall firstly take the example of Hindu religion. Hindu religion is based on CHATURVARNYAM, that is, l'our classes of Brahmins Kshatriya, Vaisya and Sudra. Thousands of years ago, Manu had laid down tha principles of CHATURVAR-NYAM in his MANUSMRITI b ok. Even now in the twentieth century, the late Guruji Golwalkar, one of Ihe founders of RSS, has hailed this CHA-TURVARNYA system in his book named Bunch of Thoughts. Even now the chief organiser of the RSS. Shri Balasaheb Deores is not denying the CHATURVARNYA system l .id down by his predecessors. Because of such orthodoxical views and blind and out-dated religious principles, some communal riots are increasing in our country,

I saw some bad communal incidents happening in Maharashtra, particularly in Pune. One Professo Kasbekar who is working in a college in Pune has written a book called "ZOT" in Marathi. In that book be has bitterly criticised the Bunch of Thoughts of Guruji Golwalkar. Tht-books of Prof. Kasbekar were kept in a stall for sale at the time of Janata Party conference at Pune. A group of young RSS workers had come there, attacked the shop destroyed the stall and torn into pieces the books of Prof. Kasbekar, only because he has critised the CHATURVARNYA system mentioned in the book Bunch of Thoughts written by Guruji Golwalkar.

The second example I found in the same city was at the time of an exhibition. There was an exhibition of God Ganapati which was arranged bv two-Professors, one Chattopadhya and another Dr. Kosambi. In that exhibition it was shown that Lord Ganapati was not thg God of a particular caste, but was a God of common people and a sympathiser of poor, backward and weaker sections among the people. Some members of the RSS went to that exhibition, broke down that exhibition and destroyed the various photo? of Lord Ganapati _____

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त :कहां कहां से ला रहे हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री आर. रामकृष्णन्): मेडन स्पीच है बोलने दीजिए ।

श्रीमति सरोज खापर्डे : आप को तो खुशी होनी चाहिए । सुनिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN); Do not interrupt him in his maiden speech.

SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Even the late Shri Agarkar, who was a well-known social reformist of Pune had attacked he dirty culture and custom of the Hindu religion. He also became a victim of such reactionary forces with communal tendencies

I also found recently the example of a young married girl from the Brahmin caste. Her young husband died in a motor accident. But the parents-in-law of that young married girl forcibly cut the hair of her head and made her to remain alone in society like a mad woman. Such is he culture, custom and education in the Hindu religion. In our country, some communal reactionary forces like Hindu Extha Andolan, Jammait-e-Islaim, Anand Marg, Patit Pavan Sangathna, all these communal organisations are trying to destroy the unity and integrity *of* our country.

The Muslim religion is also having two main groups. One is Shia and the other js Sunni. They are also exploiting the Muslim people in the name of petty reaons of religion. They have their personal law and therefore communal-minded Muslims are not pro' perly adjusting with Indian laws like Marriages Act and Family Planning, etc.

Even in Jain religion there are also two main groups: One is Digambar and the other is Shwetambar. They are having different culture and different ways because of which recently in Maharashtra State there was a serious maramari and fight between these two groups for possessing the property of God Bahubali. Even in Buddha religion also, there are original Buddhists and now converted Nava-Buddhists from Hindus in Maharashtra under the leadership of Baba Saheb Ambedkar because of the black spot of untouchability in the history of Hindu religion. They are also claiming their different cultures and mode of life. So also is the case of Indian Christians converted from Hindus. Therefore, Sir, in india we find different persons adopting different laws using their different culture and having their different customs by which these reactionary communal forces take the disadvantage of such diversity.

Therefore, Sir, for bringing all these religions together, a new set-up in the society is necessary. The law based on religion, either it may be Hindu re-
* ligion or Muslim religion or any other religion, must be removed and in its place a new law which will bind aU these religions together for the integra-
' tion of the nation must be framed for living togeher in a brotherly manner. Therefore, Sir, it is the need of the time to have such social reformative education and law. Otherwise w? daily find in India a number of communal riots and atrocities on minority by majority castes who have blind faith in bogus religious principles.

We have also found a number of murder* of innocent persons omnjit-ted in the name of religion for sacrific. ing their lives to satisfy the will of God like the Manvath incident, in which about nine innocent persons were killed in Maharashtra in the name of God. Not only this, Sir, but even young girls are forced to leave their parents* homes for God's sake and thereby these young girls are compelled to start prostitutes' business. Is it a culture, sir?

Therefore, Sir, my suggestion for the remedy on such dirty religious activities, which damage the integration of our nation, is to remove all such defects in all different religions and to make a search and investigation for solution of such complicated religious principles.

Then, Sir, about language, in India, in 1956, the States were formed on the basis of language formula but no dispute of State boundaries and language is properly solved. I am residing in Sangli city in Maharashtra which is on the border of the Karnataka State. We daily receive the news that Marathi schools in villages dominated by Mara-thi-speaking population in the Karnataka State are closed. The grants are not given. The Kannada language is imposed on Marathi-speaking students Even, Sir, young educated, unemployed persons do not get the services in Karnataka State. Therefore, on the basis of language problem the riots are started not or^y in Karnataka but their repercussions have been reflected in Maharashtra State also.

Lastly, Sir, because of such different religions, different languages and different cultures in India, the flssiparous tendencies are being created and encouraged in some parts of the country by some reactionarp and communal forces. And if they are not checked in proper time, it can harm the unity and integrity of our nation. Therefore, the Government should take immediate and effective steps for curbing this tendency by making a common law, a common religion and a common culture and education. Thank you, Sir,

SHRI NIRMAL CHATTERJEE ,We-s(Bengal): Sir, may I on behalf of those who are no longer able to make maiden speeches congratulate him for his maiden speech? And on a personal note also, since he has also mentioned two Professors, Prof. Kausambi and Prof Chattopadhaya, may I congratulate him for that reference also?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Very good. Now, Shri Jha.

श्री शिवचन्द्र झा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव सरोज खापर्डे जी का बहुत सीधा साधा प्रस्ताव है। इसमें कोई खतरा नहीं है और मैं भी कहूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को मान ले। मैं खुद कहूंगा कि यह प्रस्ताव मानने में सरकार का कोई खतरा नहीं है। सरकार को इसे मान लेना चाहिए। लेकिन क्या यह सरकार मानेगी? यदि सरकार इस प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो इसलिए कि प्रस्ताव यदि सरकार मानती है तो सरकार डाक में कटघरे में खड़ी हो जाती है। सरकार रैड हैंडेड पकड़ी जाती है। इस प्रस्ताव में कहा गया है – इम्मीडियेट एण्ड इफेक्टिव स्टेप्स सरकार ले। मतलब यह है कि आज तक सरकार ने इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया है। स्पष्ट है इसे मानने का मतलब है कि कल तक सरकार ने स्टेप्स नहीं लिये हैं, सरकार खुद कबूल करती है। यदि प्रस्ताविका कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव स्टेप लिए जाएं तो मैं कहूंगा कि यह भी सरकार नहीं मानेगी। वह इसलिए कि सरकार के सामने कोई दर्शन ही नहीं है इफेक्टिव स्टेप के लिए। यह सरकार बिल्कुल दर्शन-विहीन है। जो मुद्दे आपने उठाये यहां रिलीजन के हों या कल्चर के इन सबों को लेकर फिसिपेरस टेंडेंसीज को बढ़ावा मिल रहा है, उनके लिए सरकार का कोई दर्शन नहीं है। मैं मोटे दर्शन के मुतल्लिक कहना चाहूंगा, आम दर्शन में जाऊंगा तो लम्बा समय लगेगा लेकिन जो मुद्दे यहां उठाये गये, उन्हीं के मुतल्लिक मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, रिलीजन का इन्होंने मामला उठाया। रिलिजन का बड़ा रूप है। उसमें न जाकर जिन कारणों से मूल बीमारियां रोज ब रोज हमारे सामने आती हैं चाहे वह मेरठ हो, जमशेदपुर हो, अलीगढ़ हो, जिसका जिक्र प्रस्ताविका जी ने खुद किया है। उसको मिलाकर कहा जाता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को हम प्रेक्टिस करें तो यह सब बातें नहीं होंगी। क्या सरकार के सामने सेक्युलरिज्म का नक्शा साफ है। न दर्शन साफ है किस को कहते हैं सेक्युलरिज्म। क्या सेक्युलरिजम का मतलब वही है जो कुछ दिन पहले मैंने कहा था। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है आप अपनी सेंस और नानसेंस रिलीजन के सामने प्रेक्टिस करें और हमारी जो सेंस और नानसेंस रिलिजन है उसके सामने हम प्रेक्टिस करें। आप मुझ को दखल न दें और मैं आपको दखल न दूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह दर्शन है या नहीं? अपना अपना करो किसी को छेड़ो नहीं। एक रिलिजन का रूप इधर है और एक रिलिजन का रूप उधर है। उसका यदि साइंटिफिक रूप नहीं होता तो आप अपना प्रेक्टिस करें और मैं अपनी प्रेक्टिस करता हूं तो कलेश होगा ही। लेकिन सेक्युलरिज्म का दर्शन हमारे समाज में रहा है, यह आज से नहीं सैकड़ों वर्षों पहले से। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सेक्युलरिज्म का दर्शन खुद प्रधानमंत्री जी ने यहां नहीं बाहर किया था। सोफिया युनिवर्सिटी में जब उनको मुफ्त की डिग्री मिल रही थी, पी.एच.डी. की डिग्री मिल रही थी, डी. लिट. की डिग्री मिल रही थी। डिग्री मिलने के बाद उन्होंने उपदेश दिया। रेडियो में मैंने सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उपदेश दिया था कबीर का। वह उपदेश कबीर का मुझे बहुत अच्छा लगा। कबीर ने क्या कहा कि:

> पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
> दो पाटन के बीच में पिस गयो संसार।

एक खेमे के लिए तो यह कहा गया और दूसरे खेमे के लिए यह कहा गया था कि:

> आंकड़-कांकड़ जोड़ कर मस्जिद लइ बनाए,
> ता चढ़ि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय।

यह है सेक्युलरिजम की आधारशिला । बाहर में कहती हैं लेकिन अंदर में इसका प्रचार नहीं होता है। इसकी वजह है कि सरकार की नीति । सरकार की नीति ऐसी है कि हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और । ऐसा ही इनका प्रचार होता है ।

श्रीमती सरोज खापर्डे: आप ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री शिव चन्द्र झा: इसके मुताल्लिक दर्शन साफ नहीं है। इसलिए क्या होगा कि सेक्युलरिजम का ढोल पीटेंगे लेकिन कभी आयेगा मेरठ, कभी आएगा अलीगढ़, कभी आएगा जमशेदपुर और कभी आएगा मुरादाबाद और फिर दूसरा अफेक्ट सामने होगा।

दूसरे लैंग्वेज की बात आई है। क्या लैंग्वेज के मुताल्लिक सरकार का दर्शन साफ है, दृष्टिकोण साफ है? मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं। कल ही थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर दो घंटे बहस हुई। हमारा थ्री लैंग्वेज फार्मूला पढ़ाई के लिए जो है वह दिल्ली में लागू नहीं हो रहा है। यह कल मैंने कहा था कि इसको लागू नहीं किया जा रहा है। दक्षिण को छोड़ दीजिए और दूसरे अहिन्दी प्रांतों को छोड़ दीजिए। वहां तो इनका दृष्टिकोण ही चौपट है। बहुत सी भाषाएं हैं, उन्नत भाषाएं हैं । उनकी मांग है कि उनको मान्यता दी जाए संविधान की अनुसूची में। जैसे मैथिली है। तीन करोड़ से ज्यादा लोग बिहार में ही नहीं, सारे देश में बोलते हैं। यह कह सकते हैं कि चार करोड़ लोग बोलते हैं। इसका अनुवाद रशिया भाषा में हुआ है।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Jha, I support you on this.

श्री शिवचन्द्र झा: इसका अनुवाद रूसी भाषा में हुआ है। जब मैं मास्को गया था तो विद्यापति जो राइटर हैं उनकी कविताओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया गया । मैंने वहां जाकर पूछा कि विद्यापति में ऐसी कौन सी बात थी जो आपने इसको ट्रांसलेट किया?

इसका ट्रांसलेशन रूसी भाषा में किया गया है। लैंग्वेज के संदर्भ में मैं यह बात कह रहा हूं। विद्यापति की कविताएं रूसी भाषा में ट्रांसलेट की गई हैं। मैंने उनसे पूछा कि कम्युनिस्ट थ्योरी के संदर्भ में इसका क्या महत्व है ? तो कहने लगे कि नई पीढ़ी लव गीत पसन्द करती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चार करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको आप कब तक इग्नोर कर सकते हैं ? आप जानते हैं कि आसाम में तूफान मचा हुआ है और दूसरी जगहों पर तूफान खड़ा हो सकता है । पंजाब के अन्दर एक स्थिति पैदा हो गई है। सरकार इनको कब तक रोकेगी? अगर बिहार के चार करोड़ लोग भी खड़े हो जाएंगे और तूफान मचा देंगे तो फिर आपके लिए कहीं भी जगह नहीं रहेगी। आपका कोई भाषा दर्शन नहीं है, लैंग्वेज दर्शन नहीं है।

कल्चर के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि कल्चर का क्या मतलब होता है, क्या इन लोगों को पता है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अन्डमान निकोबार गया था। वहां पर तीन कबीले हैं ओंगी, सेन्टानीज और जरावा। सरकार कहती है कि ये लोग हॉस्टाइल हैं। इनको भारतीय कल्चर में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों की अपनी आइडेंटिटी है। यह ठीक है कि वे लोग अच्छा खाना नहीं खाते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक जमाना था जब आर्य लोग भी कपड़े नहीं पहनते थे। क्या आर्यों की कोई कल्चर नहीं थी ओंगी, सान्टानीज और जरावा, ये वहां के कबीले हैं। यह कहना कि वे लोग हॉस्टायल हैं, ठीक नहीं है। क्या हम लोग यहां पर सरकार के विरूद्ध हॉस्टायल नहीं हैं? सुबह से शाम तक सरकार का विरोध करते रहते हैं। हॉस्टायल हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि हम उनको छोड़ दें। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमारा कल्चरल दर्शन साफ होना चाहिए। मैं इस विषय पर विचार करते समय इस वक्त इन्टर कास्ट शादि को छोड़ देता हूं । हमारी जो शिक्षा की नीति है वह साफ नहीं है। आपकी शिक्षा की नीति इसलिए साफ नहीं है कि जब तक शिक्षा का आप सांइटिफिक ढंग से राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक आपकी शिक्षा की नीति

[श्री शिव चन्द्र झा]

साफ नहीं हो सकती है। अभी तक आप पुराने तरीके से चल रहे हैं। आज हमारे देश में जरूरत इस बात की है कि स्कूलों में गांधी, मार्क्स और आइंस्टाइन, इन तीनों को कम्पलसरी तौर पर पढ़ाया जाये । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गांधी, मार्क्स, आइंस्टाइन और डार्विन को बच्चों को कम्पलसरी तौर पर पढ़ाया जाय। इससे दृष्टिकोण बदलेगा । डार्विन को पढ़ने से वे समाज को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अभी हम देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग की बहुत बातें की जाती हैं । रेडियो और टेलीविजन पर इनका प्रचार होता है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब लोगों को और हमारे बच्चों को डार्विन के सिद्धान्तों की जानकारी होगी और वे डार्विन को पढ़ेंगे . . .

मार्क्स को नहीं पढ़ेंगे, आइंस्टीन को नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों का दृष्टिकोण साफ नहीं होगा। इसलिए उनको कम्पलसरी, मार्क्स का मतलब होता है कि लेनिन भी उसमें है, कहने का मतलब कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को भी पढ़ाया जाये । यह शिक्षा, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं जनता के सामने पहुंचाने का जो माध्यम है वह प्रेस है । प्रेस के मुतलिक आज जब बिहार प्रेस बिल आता है तो एक बवंडर खड़ा हो जाता है जिसमें कोई सेंस नहीं है। जगन्नाथ मिश्र कोई ज्ञान कोई अकल है नहीं । प्रेस फ्रीडम के बारे में उनको पता नहीं है। मैंने लिखा है यही सब, इन्डियन नेशन में 19 तारीख को। मेरा लेख है कि चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा हैज नो नालेज आफ फ्रीडम आफ प्रेस । उनको उसका ज्ञान ही नहीं है और यह बवंडर उठा रखा है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, दोनों तरफ की बातें यस-नो, नो-यस जो होता है । लेकिन कामन सेंस की बात है कि यह समाज के खिलाफ बात जा रही है। एक कामन सेंस कभी कभी आप अपने को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब मौका पड़ता है। अब मैं आपको उदाहरण दे दूं। आप भी जानते हैं कि मोरारजी भाई को निकालना था इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और एक ऐसा इश्यू बनाया देश में कि सारे देश की हवा ही दूसरी हो गई। प्रीवी पर्स की बात ले ली और लोग उनके साथ लग गये, हवा ही उनके पक्ष में हो गई। ऐसे इश्यू जब अपने को मजबूत करना होता है तब तो बनाना होता है लेकिन प्रेस के मुत्तलिक उनका जो स्टैंड है वह साफ नहीं है। भारत की प्रेस आजाद नहीं है। भारत की प्रेस उसी रूप में है जिस रूप में अमेरिका और इग्लैन्ड की प्रेस है। वहां भी यलो प्रैस है, यहां भी यलो प्रेस है। अमेरिका का प्रेस ज्यादा यलो है, इग्लैंड का प्रेस ज्यादा यलो है। यह अभी उस से सीख रहा है, अभी थोड़ा है जैसा अभी हमारा देश अविकसित है, प्रेस, यलो प्रेस उसी रूप में अविकसित है, अन-डेवलप्ड है, लेकिन यलो है। इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रेस को आप प्लान्ड करें । मैं इस बारे में जब मैंने अपना विधेयक पेश किया था तो बहस कर चुका हूं और इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन प्रेस स्वातंत्र्य, प्रैस की फ्रीडम को बढ़ाने के लिए

सारे प्रेस को आपको प्लान्ड करना होगा, प्लान्ड प्रेस और पार्टी प्रेस । आप उसको अपने प्लानिंग कमीशन के मातहत ले लें और उसके नीचे रहने दें । यह एक बहुत बड़ा माध्यम है और इस माध्यम से जो कुछ भी आप काम करें, सरकार जो कुछ भी काम करेगी वह जनता में जायेगा । वह बात जनता तक जानी चाहिए जिन बातों को आप सोचते हैं । लेकिन यह सरकार बिल्कुल चौपट है, इसके पास कोई दर्शन ही नहीं है । यदि इन प्रश्नों की सफाई हो जाती है तो बात साफ हो जाती है और तब मैं मान सकता हूं कि हमारा जो मीडियम है वह सशक्त होगा । लेकिन इस रूप में सरकार इसको करेगी नहीं । मैं चाहता हूं कि आप नीति के तौर पर इसको मान लीजिए । लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको मान लेते हैं तो आप कटघरे में खड़े हो जाते हैं, यू रिमेन कन्डेम्ड । इसके बिना जितने भी काम होंगे समाज की प्रगति में, उनमें उस रूप में तेजी नहीं आयेगी । आपने एक दूसरी ही फिजा बना दी क्योंकि ये जो सब बातें बन्द हुई इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है । बीच में ढाई साल जनता सरकार सत्ता में रही, उसको माइनस कर लीजिए । उसने इस छोटे से पीरियड में बहुत कुछ सुधारने की कोशिश की । ...(व्यवधान) . जनता सरकार

4 P.M.

...(व्यवधान) .. आज इतना बीस सूत्री कार्यक्रम का ढोल पीटने के बाद जो विकास हो रहा है वह पूंजीवाद का विकास हो रहा है । अमरीकी पूंजीवाद का जाल फैलाया जा रहा है और सरकार इस संशोधन के बाद, उस संशोधन के बाद मैदान साफ कर रही है उनके इनवेस्टमेंट के लिए । तो सारा आपका मैस्स जो है देश में यह संकट जो है इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से है । जब तक गलत नीतियों में, बुनियादी नीतियों में परिवर्तन नहीं होता है तो आप चाहे जो भी कर लें कुछ भी इफेक्टिव होने की सम्भावना नहीं है लेकिन बावजूद इसके सरकार इसको इसी रूप में मान लें । इन्हीं शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम भगत पासवान (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सदस्या महोदया समय के अनुसार एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लाई हैं इसका तहेदिल से मैं समर्थन करता हूं । ठीक है कि आजादी के बाद 35 वर्ष हो रहे हैं फिर भी हमारे समाज के अन्दर जाति-पाति, भाषा, धर्म के नाम पर अनेकों मानवता पर कुठाराघात हो रहे हैं। एक तरफ हम दावा करते हैं कि यह देश मानवता के पुजारियों का देश है और वास्तव में रहा है। यहां का ज्ञान दूसरे देशों में प्रचार हुआ लेकिन अभी भी हमारे देश के शुभचिन्तक जो लोग रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चलते । इसी वास्ते मानवता जो है आज कुचली जा रही है । दंगों के बहुत से कारण हैं । सामाजिक तो हैं हो । अभी भी समाज के अन्दर जात-पात, धर्म यह समस्याएं गई नहीं हैं । हम लोगों को यह आशा थी कि विज्ञान की प्रगति हो रही है विस्तार हो रहा है तो यह जो बातें हैं यह घटेंगी यह साम्प्रादायिक दंगे कम होंगे । लेकिन बहुत से समाज में ऐसे पाखंडी लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर जाति के नाम पर एक दूसरे को धृणा की दृष्टि से देखते हैं तब दंगे होते हैं । सामाजिक कारणों से भी दंगे हो रहे हैं । एक तरफ हम देखते हैं कि गरीब का लड़का एम. ए. पास कर के अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त कर के सड़क पर घूमता है सौ रूपये की नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरी तरफ धनियों के बच्चे शिक्षा कुछ नहीं फिर भी वह बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं और बहुत ऐशो-आराम के साथ रहते हैं । इससे भी सामाजिक बेचैनी रहती है । हमारी सरकार ने इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं लेकिन यह हमारे असामाजिक तत्व जो हैं यह समय-समय पर विरोधी पार्टियां जो भी हैं हम ने सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए जो प्रयास किए हैं उसमें यह लोग बाधा डालते हैं । हमारी सरकार ने भूमि सीमा हदबन्दी के अनुसार बहुत सी भूमियां वितरत की लेकिन जो जनता पार्टी की सरकार आई तो सबों से भूमि छीन ली गई और जो गरीब भूमि पर कब्जा जमाने के लिए गये तो उनकी हत्याएं हुईं । श्रीमन्, इस

[श्री राम भगत पासवान]

विषय में बिहार की कितनी ही मिसालें हैं । बेलछी का कांड हुआ, धर्मपुरा, पथरीडीह, पिपरा का कांड हुआ। इन सब में हर जगह मजदूरों के चलते या भूमि के जो पर्चे उनको मिले थे उन पर्चों के अनुसार अपना कब्जा जमाने गए तो यह हत्या-कांड हुए । बोंडेड लेबर के चलते कि बांडेड लेबर समाप्त होनी चाहिए इस के चलते समाज के बड़े लोगों ने कुठाराघात किया । तो यह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण भी है । यह दंगे फसाद हो रहे हैं । इसके लिए हम विरोधी पार्टी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि वे इस प्रकार के दंगे न होने देने के लिए सहयोग दें । समाज में जो बेचैनी है उसको समाप्त किया जा सके । हम देखते हैं कि जिनके पास प्रापर्टी है उन्हीं के पास बिजनेस है, सिनेमा हाल भी हैं । उन्हीं के लड़के बड़ी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर के बड़ी बड़ी सर्विसेज में हैं और दूसरी तरफ वह आदमी हैं जिन-के पास न घर है, न कोई रोजगार की गारंटी है । यह भी समाज में आर्थिक विषमता है इसके चलते समाज में कलह हो रहा है दंगों और बेचैनी का क्या कारण है ?

हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्म एक दूसरे को आदर की दृष्टि से देखें लेकिन आज अभी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां आज हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है । अभी शिव चन्द्र झा जी बहुत बोल गए, उन्होंने भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर कहां ... **(समय की घंटी)** कि बहुत विषमता है . . . . . **(व्यवधान)** आज सवाल यह है कि जो समाज में बेसिक परिर्वतन आना चाहिए उस बेसिक परिर्वतन के लाने के ठेकेदार कौन हैं तो उन लोगों को भी अपनी मनो-वृति बदलनी चाहिए ताकि आज समाज में सभी को आदर की दृष्टि से देखा जए । महातमा गांधी जी ने कहा है :-

"सर्व जन: सुखीना, संतोष समस्त मंगलानि" सभी सुखी हों, सभी को रोजी रोटी मिले, सभी आनन्द में रहें, सभी एक दूसरे को आदर की दृष्टि से देखें, ऐसी भावना समाज में आनी चाहिए । यह भावना ही नहीं आयेगी तब तो हम सिर्फ यह सिद्धांत ही जड़ते रहें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह देश मानवता के पुजारियों का देश है, **(समय की घंटी)** अब भाषाओं से काम चलने की नहीं है, खाली नीति की दुहाई देकर भाषाओं से काम नहीं चलेगा । अब तो ऐसा दिन आ गया है 'भूखे पेट भजन न होय गोपाला, लिए हाथ में कण्ठी माला' जब तक वह भूखा है जब तक उसको रोजी रोटी नहीं देते जब तक इसमें समानता नहीं आती है तब तक सामाजिक समानता भी आना सम्भव नहीं है । इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो आर्थिक विषमता है, इसके चलते भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं और ये जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर दंगे हो रहे हैं । इनके पीछे जो अराजक तत्व हैं असामाजिक तत्व हैं वास्तव में ये हमारे देश की अखण्डता पर और हमारे देश की संस्कृति पर कुठाराघात करना चाहते हैं। इनको अच्छी तरह से दबा देना चाहिये ताकि समाज में खुशहाली रहे । जब समाज एक दूसरे को आदर की दृष्टि से देखें और अपने राष्ट्र के प्रति सबों की वफा-दारी रहे । यह कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं और आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Mr. Vice-Chairman, Jast for my information, are you not going to allow the speakers to speak—because such an important Resolution has been moved?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Mr. Kulkarni, unfortunately you were not there. I have taken the House into confidence on more than one occasion today and there is no consensus in the House. Some people want to conclude i* today and some people just want to take their own time—in view of the importance—including th$_e$ person on your left, th$_e$ honourable Mr. Goswami.

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): We are with Mr. Goswami.

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती, सरोज खापर्डे को बहुत ही साधुवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा प्रस्ताव इस सदन में लाई हैं और मैं उनके साथ और इस प्रस्ताव के साथ पूरी तौर से सहमत हूं । यह बात बिल्कुल सही है कि 35 वर्षों की आजादी के बाद भी आज तक अगर हम इसमें सफल नहीं हो पाये हैं तो इसका कारण है सरकारी जो यंत्र है बिल्कुल उसकी निष्फलता । क्योंकि हमारे भाई गोस्वामी जी ने बहुत ही सही कहा था कि प्रशासन में हमारा क्या दृष्टिकोण है । हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह का प्रशासन कर रहे हैं, यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम दंगे, फसाद या इस तरह के लोगों में जो अलगाव की भावना है, उसको दबाकर रख सकें । आज दंगों की सारी वारदातें होती हैं परन्तु अगर आप सभी दंगों की जड़ में जायेंगे तो दंगे की जड़ में अधिक यही पायेंगे कि सरकार के द्वारा कोई गलत नीति हुई या वहां की स्थानीय सरकार ने कभी कभी उनके मसले को हल करने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसको टालती रही । कहीं पर चाहे पूजा के स्थान को ले करके झगड़ा हो, चाहे इनके मंदिर की जमीन को लेकर झगड़ा हो, कहीं पर घर पर कब्जा करने का झगड़ा हो या शिक्षा के स्थान पर कब्जा करने का झगड़ा हो, ये सब बातें होती हैं और जब साल, दो साल, चार साल के बाद भी वह झगड़ा नहीं निपटता है तो अंत में एक दिन वह फसाद का स्वरूप ले लेता है । फिर इसमें चाहे मेरठ की बात हो चाहे बिहार शरीफ की बात हो चाहे मुंगेर के बंगलवा काण्ड की बात हो, इन सारी बातों की जड़ वही है । प्रशासन फेल होता है और जिस समय उन्हें हल करना चाहिए वे हल नहीं कर पाते हैं तब इसके कारण दंगे की बात आती है । दूसरी बात यह भी है कि आज भी कुछ राजनैतिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी इस बात को, साम्प्रदायिकता को बढावा देना चाहती है । वह इस लिए बढ़ावा देना चाहती है कि वह अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहती है और राजनैतिक उल्लू इस लिए सीधा करना चाहती है कि वह किसी खास ग्रुप को अलग रखना चाहती है ताकि दो-चार ग्रुप अलग-अलग रहें और चुनाव के समय किस को किस के साथ मिला कर भिड़ाया जाये जिस से उन का काम चल जाये । कभी भी स्वस्थ नीति उन की नहीं रही कि दंगा-फसाद न हो । जो अंग्रेजों की पालिसी की बात श्रीमती सरोज खापर्डे ने कही डिवाइड एंड रूल की वही डिवाइड एंड रूल आज भी चल रहा है ।

हमारे कुछ भाइयों ने आर. एस. एस. का नाम लिया । यह कहना बहुत आसान है । इस समय हालत यह है कि नींद में सोए हुए भी ड्रीम के अन्दर किसी को लगे कि दंगा हुआ तो आंख खुलेगी तो बोलेंगे कि आर. एस. एस. वालों ने दंगा किया । इस तरह का प्रचार, इस तरह की झूठी-झूठी बातें कही जाती हैं । कहीं आज तक इस तरह का उदाहरण मिला कि आर. एस. एस. वालों ने प्लान किया ? क्यों झगड़ा करेंगे ? क्या हिन्दुस्तान में जो 11 करोड़ मुसलमान हैं वह भाग जाएंगे, क्या उन की हत्या कर दी जायेगी ? यह बिलकुल गलत बात है । इस तरह का झूठा प्रचार नहीं करना चाहिये । अगर आर. एस .एस. के गुरू गोलवलकर ने बंच आफ थाट्स में चातुर्वर्ण की बात लिखी तो उन की बात है । इस तरह की बात मानने वाले आज भी हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग हैं । चातुर्वर्ण क्या है ? ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र--समाज को चार रूप में बांटा गया था काम के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं । जन्म के अनुसार आज लोग मानने लगे हैं । उन्होंने कह दिया कि पूना में जनता पार्टी के समय गुरूजी के 'बंच आफ थाट्स' को ले कर झगड़ा हुआ था । अब वहां कांग्रेस रूल के समय झगड़ा हुआ । यहां की बात को वहां जोड़ने का क्या मतलब है ? इस लिए कि आर. एस. एस. का नाम आ जायें । इस तरह का प्रचार न करें मुझे बहुत दुख हुआ । मैं मुंगेर में था । बंगलवा में दंगा हुआ । वहां मुसल-

[श्री राम लखन प्रसाद गुप्त]

मानों की हत्याएं भी हुईं, लेकिन वहां दंगा शुरू किया मुसलमानों ने। मुसलमानों ने एक हिन्दू की हत्या कर दी। मैं इसे ठीक नहीं कहता। कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टेटमेंट दे दिया कि बंगलवा में आर. एस. एस. का हाथ था। न वहां आर. एस. एस. की ब्रांच है, न कुछ है, लेकिन उस ने स्टेटमेन्ट दे दिया। यह जो इस तरह रजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को बदनाम करने का तरीका है इस से काम नहीं चलेगा। जो भी दोषी व्यक्ति हो उस को पूरी-पूरी सजा मिलनी चाहिए। गलत आदमी को दोष नहीं देना चाहिए। इस लिए मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह प्रशासन की दृष्टि से कहीं पर किसी तरह का मामला उठता हो तो उस के ऊपर तुरन्त कार्यवाही करे और कार्यवाही कर के शान्त करे।

दूसरी बात यह है, कि जहां तक भाषा का सवाल है, यह बात भी सही है कि भाषा के विषय में बहुत तरह की बात कहीं जाती है। अगर हम सभी भाषाओं को मान्यता नहीं देंगे तो भाषा का सवाल कैसे हल हो सकता है, जैसे भी लेंग्वेज फार्मूला की बात हुई, उस को चलाओ, लेकिन आप थ्री लेंग्वेज फार्मूला बना कर चुप बैठ जाएंगे और जब काफी झगड़ा होगा, दो-चार सौ आदमियों की जान जायेगी फिर आप सोचेंगे। अगर आप यह फार्मूला लगा दें तो बहुत कम लोगों को ग्रीवानस रह जायेगा लेंग्वेज के मामले पर। इस लिए मैं यही कहूंगा कि इस प्रस्ताव को मैं समर्थन देता हूं और मंत्री महोदय को इस तरह ध्यान देना चाहिए कि सारे राजनीतिक कारण हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण है, इस कारण यह मामला हल नहीं हो रहा है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि इस का पूर्ण दोष कांग्रेस (आई) वालों पर है।

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, there could not be a more timely Resolution than this at this juncture when India is facing a very serious threat to her security on account of the induction of sophisticated weapons by the United States into Pakistan. There is already a gathering storm ol danger across the frontiers of India, and we are lacing that danger at this juncture.

No doubt, the regional sentiments, the linguistic pride and the cultural affinity constitute a national phenomenon in a vast country as India which takes legitimate pride in her diversity in unity. This phenomenon, to my mind, is not limited only to big countries. It is seen even in muc'h smalle r countries as well. Take, for instance, the Great Britain. The strong regional and linguistic sentiments have persisted in Scotland and Wales for centuries, but they have not eroded the unity of the Great Britain. Take for instance, Canada. The friction between the French-speaking Canadians and the English-speaking Canadians continues, but Canada has remained one piece. There have been countries in the history of the world where linguistic or cultural or social or economic differences led to civil wars, and ultimately the unity of the nations had to be retained by resort to arms. This is what happened in the 19th century in the United States of America.

It has been said Sir, that the unity was the gift of the British to India. This is not quite correct. The other day, one hon. Member, and if I remember correctly it was Mr. Piloo Mody, said that there were Gujarat is, Assamese, Punjabis and so on in this country but no Indians. This, Mr. Vice-Chairman, Sir is a fashionable view. But it is too superficial to be accepted. In its long chequered history spreading over thousands of years, India witnessed political unity more than once. Taking one example only, during the days of Ashoka the frontiers of India stretched far very deep in the South to beyond the banks of the Indus. But spiritually India was always a single entity. It was the invisible bonds of t(he spirit of tolerance and the remarkable capacity of India to absorb different cultures, thoughts and civilisations which kept India a single country throughout the chequered history of thousands of years. But this

is also right to some extent that when India disintegrated politically on the decline of the Moghul Empire, it was the British who brought about the reunification of India politically, first by force of arms and later by the establishment of a strong central authority, backed by the modern means of communication.

Sir it is at this juncture that a new development arose and emerged on the political horizon of India. Strong political elements actuated by personal ambitions and vested interests sought to arouse the communal frenzy of a section of people in this country in order to gain access to political power, and the tragic consequences of their actions is how a part of India's tragic history. India was broken into two pieces. India was torn apart even geographically which India had never done in thousands of years of her history.

The most alarming factor today is that some political forces have once again arisen on the Indian political scene and have started whipping up communal passions and frenzied emotions over linguistic and regional differences in order to Paralyse the duly elected governments of the day, in order to attain political power outside tfye constitutional framework. It is these forces which at present are causing a threat to the security, to the unity and the integrity of India.

Sir_ I believe that what holds India together today is its democratic institutions, its concept of secularism which reflects the wisdom, the thought, the civilization of India gained over centuries and the will and authority of its duly elected governments to uphold and preserve the institutions and the ideals of the nation. It is these forces which have started hitting out at these pillars of democracy in this country. What is democracy? The foundation of demoraey is the promises that a government which is elected by the people will be given a chance to govern the country for the period which is prescribed by the Constitution. No democracy can last if the political parties which are defeated at the polls refuse to accept the verdict of the people and seek to paralyse the duly elected governments of the day in order to wren/Ch political power by resorting to means intended to create chaos in the country. In this regard, Sir, I will seek liberty to refer to the words of Abraham Lincoln which he addressed to the people of the South when they were bent upon secession I quote:

"We everywhere express devotion to the Constitution. I believe there is no difference in this respect, whether on this or on the other side of this majestic stream. The question is as to what the Constitution means. 'What are their rights under the Constitution? That is all. To decide that who shall be the judge? Can you think of any other than the voice of the people? If the majority does not control, the minority must. Would that be right? Would that be just or generous? Assuredly not-Though the majority may be wrong in electing me yet we must adhere to the principle that the majority shall rule. By your Constitution you have another chance in four years.

In his inaugural speech delivered on March 4, 1961, he said:

"Plainly the central idea of secession is the essence of anarchy. A constitutional majority is the only true sovereign of a free people. Whoever rejects it does of necessity fly to anarchy or to despotism; the rule of a minority as a permanent arrangement is wholly inadmissible; so that rejecting the majority principle anarchy or despotism is all that is left.

Therefore, I will give, Sir^ only three examples of the mental attitude of these political forces to show how they are sapping the foundations of demo-

[Shri Madan Bhatia] cratic institutions in ihis country. Immediately after the state Assembly elections in 1980, a very prominent leader of a political party declared that Parliament had become irrelevant. There was another prominent leader who, at the time when the Assamese agitation was at its height sought to instigate the feelings of agitation and regional sentiments for political purposes by describing the people oi Assam as Assamese nation.'

And the pity is—and this is the tragic irony—that those gentlemen had been elected by the people as their representatives to the Lok Sabha and ha^ taken the oat'n by which they had sworn that they would bear true faith and allegiance to the Constitution of India and will uphold the integrity and sovereignty of India. Now what is this Akali agitation? It will be wrong— and I was hearing some speeches last week of some of the honourable Members which seem to suggest that this is an agitation of the Sikhs. It is not an agitation of the Sikhs. The Akali Party is not the sole exponent pi the Sikhs in Punjab. It is an agitation launched by the Akali Party after it lost power in 1980. The rationale of this agitation in the Anandpur Sahib resolution which was passed in 1973 when the Akali Party was not in pewer. It was resurrected in 1980 when it had lost power. And at that time the Akali Party put forth demands by giving them a religious clothing in order to whip up communal frenzy of a section of people in Punjab against chR duly elected Government of the State. It was suggested by one honourable Member in the course of the debate last week that the demands put forth by the Akali Party are too trivial and laughable not to be conceded. I believe those demands are laughable but they are certainly not trivial. They strike at the very roots of the concept of secularism which is embodied in our Constitution and as the law stands today, even Parliament has no power to make any law which offends the principle of secularism as enshrined in the Constitution. Taking jus. two demands which were referred to by the honourable Member, the first demand is that a particular train should be named as Harmandir train. The other demand is that Amritsar should be declared as a holy city. In order to understand the constitutionally of these demands, they have to be taken to the logical extreme. Take the first demand first: Supposing one day, one fine morning the Government issues a flat or Parliament make., a law, saying that all the trains in this country will be made after Hindu gods, will it be a constitutional act or a constitutional step? Certainly not because it will be against the concept of secularism which means not merely that the State shall not discriminate on account of religion and shall not interfere with the religious freedom but the State shall not promote any particular religion or religious practice. Taking the second demand that Amritsar should be declared a holy city, if this demand is to be taken to its logical conclusion, then the Executive or Parliament of this country will have the power to declare the whole of India one day as a holy country. Surely it will not be constitutional', because there is a rider on the power of the Executive and Parliament under the Constitution. Secularism is the basic concept. It cannot be altered or amended even by Parliament by an amendment of the Constitution, mucfh less by an ordinary statute. Such a demand will be open to two other objections. It will seriously infringe the personal liberty of a section of people living in Amritsar. The liberty has been defined by the supreme Court as not merely freedom from incarceration but the right *to* do what one wants to do, the right to eat what one wants to eat, the right to drink what one wants to drink, the right to sleap, the right to go wherever one wants to, and so on and so forth. These rights of a section of the people in that particular place will be infringed and the Executive has no power by means of an executive flat to interfere with the liberty of a citi-

z'en under article 21 of the Constitution of India. Even Parliament cannot make this law because Parliament cannot make any law to promote religion or religious practice under the Constitution in view of the basic concept of secularism. So as to infringe the personal liberty. This is the real character oi these political forces.

The question is: where do we go from here and what are the duties of the Executive and the Parliament?

Sir we have taken a solem oath to uphold the integrity of India and to uphold its democratic institutions. The walls and portals of this House bear mute testimony to the oath that we have taken. History will never forgive us if we break it and fail to uphold the democratic institutions of this country and the democratic ideals and concept of secularism. *(Time bell-rings)* One minute please. I just want to hark back again to the words of Abraham Lincoln which he addressed to the people of the South who were threatening to go to war for secession. He said:

"During the winter just closed, I have been greatly urged by many patriotic men to lend the influence of my position to some compromise by which I was to some extent, to shift the ground upon which I had been elected. This I steadily refused. I so refused, not from any party wan-tonness^ nor from any indifference, trouble of fhe country. I thought such refusal was demanded by the view that if, when a Chief Magistrate is constitutionally elected, he cannot be inaugurated till he betrays those who elected him, by breaking his pledges and surrendering to those who tried and failed to defeat him at the polls. This Government and all popular Government, is already at an end. Demands for such surrender..."

These words are important for some hon. Members who have suggested that there should be negotiation.

... Demands for such surrender, once recognised, are without limit, as to nature, extent and repetition. They break the only bond of faith between public and public servant; and they distinctly set the minority over the majority.

In your language, my dissatisfied fellow countrymen and not in mino is the momentous issue of civil war. The Government will not assail you, unless you first assailed, you can have no conflict, without being yourselves the aggressors. You have no oath registered in heaven to destroy the Government, while I shall have the most solemn one to preserve and defend it. You can forbear the assault upon it; I cannot shrink from the defence of it."

I respectfully submit, Sir, that the time has come when the Executive and the Parliament have to declare that the Constitutional institutions of the nation, its ideals and secularism are not negotiable. They cannot be negotiated without disintegration of the country. And if my voice can be carried to my countrymen across the walls of this House, I appeal to all of them, particularly the intelligentsia of this country, the teachers, the professors, the lawyers, the doctors, the businessmen the executives and the educated farmers to arise and raise their powerful voice against the political hypocrisy of these forces which are seeking to destroy the democratic institutions of this country by hiding their real objective.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, कुमारी सरोज खापर्डे जी का यह जो मंसूबा है, बहुत अच्छा इस मामले में है क्यों कि ऐसी चीजों पर सदन को चर्चा करने का मौका नहीं मिलता। यह घुमाफिरा कर हमारे देश की आंतरिक नीति से जुड़ा हुआ है। देश

[श्री लाडली मोहन निगम]

की अंतरिक नीति जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब बिल्कुल साफ है कि घर मंत्रालय और उसके साथ सारी सरकार के कार्यकलाप इसमें आते हैं। सवाल यह है कि, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहता, केवल एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह कि मनुष्य की अपनी एक खुद की फितरत होती है और उसके विकास के नाम पर जिस तरह से हम लोगों ने समाज को अपने हित के लिये इस्तैमाल किया उसके फलस्वरूप आज नई नई समस्यायें खड़ी हो रही हैं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि दो ही चीजें हैं मनुष्य और प्रकृति। एक सबसे खड़ी खामी जो इंसान की फितरत रही है वह यह है कि इंसान ने हमेशा यह कोशिश की है कि किसी न किसी तरह वह कुदरत पर कब्जा कर ले। उसने कुदरत पर लगाम लगाने की कोशिश की। जब मनुष्य ... ऐसा बन गया कि प्रकृति से वह ऊपर है प्रकृति के साथ उसे नहीं चलना चाहिए और उसको प्रकृति पर कबजा कर लेना चाहिए तो बिल्कुल साफ है कि इससे उसकी जो फितरत है वह विकसित होगी और जब आदमी अकेला रहता होगा तो उसके धीरे धीरे उसने यह सोचना शुरू किया होगा और उसके मन में यह धारणा आई होगी कि किसी न किसी तरह प्रकृति पर कब्जा करना चाहिए और तब कहीं न कहीं उसके मन में एक स्थायित्व नहीं बल्कि सम्पति का सपना जगा होगा। आज समाज में जो विकृतियां पैदा हुई हैं उनका कारण यह है कि मनुष्य ने अपने मन में सम्पति की धारणायें बना ली है और उसके बारे में उसके दिमाग में कोई विचार बन गया और उस सम्पति को लेने के लिए वह येन केन प्रकारेण लालायित है चाहे वह समाज की सम्पति हो, चाहे वह सत्ता की सम्पति हो और चाहे वह खुद की सम्पति हो। उस सम्पति पर येन केन प्रकारेण अपने हित में और अपने कुनबे के हित के लिये कोशिश करना चाहता है। तो बिल्कुल साफ है कि मामला लड़खड़ा गया और जबर्दस्त विरोध के बाद, इसके चलते जब मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू किया तो असमानता पैदा होना शुरू हुई और अगर आज के प्रस्ताव के मूल में हम जायें तो मुझे एक चीज नजर आती है। ठीक है, आजादी के पहले हम कह सकते हैं कि हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज और उसके पहले और भी ताकतें राजा-महाराजा, तरह तरह के सब लोग आये और इन लोगों ने अपने हित के लिये लोगों का शोषण किया। लेकिन आजादी के बाद तो कम से कम देश की अपनी जहनीयत बननी चाहिए थी लेकिन वह कहीं परिलक्षित नहीं होती। बल्कि मैं यह मानकर चलता हूं कि आज जो आर्थिक असमानता है उसमें इतनी ज्यादा दूरी हो गई है एक दूसरे के बीच में इतनी दूरी हो गई है कि इस असह्य सीमा को पार करना मुश्किल है और जब असह्य हो जाता है तब साफ है कि आदमी कहीं न कहीं विस्फोट करेगा। एक बच्चा है और आप उसकी बात को नहीं सुनना चाहते तो पहले वह बचपन में जब बोलना नहीं जानता तो वह चिल्लाता है। जब कुछ बड़ा होता है तो मां को खीचने लगता है। जब थोड़ी और चेतना बच्चे में जागृत होती है तब वह कर कुछ नहीं सकता चीजें उठाकर फेंकता है और यह उसके अन्तर्मन का विद्रोह है। जो अपने विचारों के साथ समझौता करना नहीं चाहता, कर नहीं सकता क्योंकि उसके विचारों को समझने की आप में कुव्वत नहीं है। यही हालत आज के सत्ताधारियों की है। देश के मन की भावना क्या है, देश को किधर ले जाना है, देश को क्या बनाना है इसकी कोई परिकल्पना उनके पास नहीं है। इनके पास एक ही परिकल्पना है और जैसा अभी हमारे मोहतरिम दोस्त कह रहे थे, उन्होंने प्रजातंत्र की एक बड़ी अजीब परिभाषा कर दी। इतना याद रखिये कि जिंदा कौमें पांच वर्ष तक इंतजार नहीं करतीं। राष्ट्र और जीवित राष्ट्र में पक्ष और विपक्ष की बराबर अभिव्यक्ति होती रहती हैं। पांच वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष तक किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष दल के नाम पर कोई मौरूसी पट्टा नहीं लिखा रहता। अटूट बहुमत होने के बाद भी अगर सिर्फ बहुमत के नाम पर आप अपने मन में यह सोचते हैं कि पांच वर्षों के लिये मौरूसी पट्टा मिल गया है...

और व्यक्ति की असहमति की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया तो फिर स्वाभाविक है कि तनाव होगा और यह तनाव आन्तरिक सरकार की व्यवस्था का तनाव, आर्थिक विकास का तनाव, सामाजिक विषमता का तनाव है इन तनावों के रहते मनुष्य का मस्तिक कैसे संतुलित रहेगा। यह मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। अभी तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ऋषि महापुरुष हो जो तनाव में भी संतुलन न खो सके तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में जिस तरह की मनोवृति बन रही है तोड़-फोड़ की प्रवृति उत्पन हो रही है इसके कारणों की खोज करने की कोशिश करें। यह कारण जब हम खोजने जाएंगे तो कहीं न कहीं मनुष्य को उसके साथ जुड़े हुए समाज के अन्दर पनपते हुए तनाव को हम देखना पड़ेगा। इस तनाव का कारण क्या है जो भी कोई सरकार पांच वर्ष के लिए उसको चुन लिया गया और वह अपने कार्य-कलाप से ऐसी स्थिति पैदा कर दे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच असमानता मनुष्य मनुष्य के बीच असमानता हो गई है सारे विकास का आर्थिक दमा दोहन जिस प्रकार से हुआ वह इन्हीं लोगों के लिए हुआ हो, मुट्ठी भर सम्पन्न लोगों के लिए हुआ हो एक सुविधा सम्पन्न वर्ग बन जाए। एक दो करोड़ इन्सान सम्पन्नता की जिन्दगी जीयें और 60-62 करोड़ विपन्नता की जिन्दगी जीयें। तो तनाव तो होगा ही। इसको हम कैसे तोड़ेंगे। इसके साथ सवाल है कि जब तक समता की जिन्दगी हमारी नहीं होती बराबरी की कल्पना तब तक नहीं हो सकती। जो सामाजिक तनाव है आन्तरिक तनाव है आपको रोज परिलक्षित होता है। मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान में जितनी नारी सताई गई है जितना शायद ज्यादा पिछड़े और दबे हुए लोगों को सताया गया है उतना किसी भी व्यवस्था में नहीं सताया गया है। मैं यह नहीं कहता कि अन्याय पहले नहीं होता था, होता रहा होगा, लेकिन आज के जमाने में ज्यादा है। उस जमाने में बौद्धिक अन्धकार भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था चेतना-शून्य था और वह आज कुछ चेतना की तरफ चल रहा है। उसका मन भी चेतना-शून्य नहीं है बल्कि चेतना आज जागृत हो रही है। कल के किसी हरिजन को आप जैसा चाहे दबा कर रख सकते हो लेकिन आज जिस हरिजन या आदिवासी का बच्चा चार-पांच दर्जे तक पढ़ गया है और वह पहली मर्तबा शहर में मेहनत मजदूरी के लिए शहर चला गया है वह इसके बाद वहां पर कहीं समता और बराबरी देखने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक है कि उसके मन कहे कि हम भी उसके मुकाबले बनें फिर जब उसको कुछ नहीं मिलता है प्रतिकार स्वाभाविक हिंसात्मक हो जाता है। प्रतिकार के बारे में यह कल्पना थी कि आजादी के बाद जो भी तनाव के प्रति प्रतिकार होगा समाज की समानता के प्रति प्रतिकार होगा वह प्रतिकार बोली का होगा, हिंसा का नहीं अहिंसा का होगा लेकिन अगर आप उसके रास्ते ही बंद कर देंगे जैसे अभी कल ही पढ़ रहे थे कल इतनी देर तक सदन में लोगों ने बहस की दो महीने से सन्थाल परगना में आदिवासी लोगों को रोटी नहीं मिली, दुकानों पर गल्ला नहीं मिला और उनको शान्त करने के लिए गोली और डंडा बरसाया गया। गोली से रोटी की भूख आप कम करना चाहते हैं तो कैसे हो सकती है। तात्कालिक रूप में खत्म हो जाएगी। मैं जहां से आता हूं इन्दौर मेरी राजनीति की भूमि रही है। अहिल्या बाई का नाम आपने सुना होगा। अहिल्या बाई कर के एक रानी हुई है। वह बेवा थी। वह राजगद्दी पर बैठी राज्य चला रही थीं। उसका बच्चा छोटा था। खरगोन उसके साथ जुड़ा हुआ इलाका है। वहां पर बगावत हो गई। उसके पीछे उसके कमांडर लोग गये तो उसने कहा कि मैं यह बलवा शान्त कर सकती हूं। उसने पूछा कि बलवा क्यों है। तो उसको बताया गया कि इस साल फसल नहीं पकी है इसलिए लोग निकल पड़े हैं। सरकार के गोदाम पर जाना चाहते हैं। उसने कहा कि इस दंगे को मैं रोकूंगी। फौज उसके पीछे चल पड़ी और फौज की गाड़ियों में उसने हथियार या बन्दूकें नहीं लदवाई, तोप

[श्री लाडली मोहन निगम]

नहीं थी लेकिन अनाज की बोरियां लाद कर के वह पहुंच गई भीड़ के पास और तब एक दम दंगा खत्म हुआ। सवाल यह है दृष्टि हमारी क्या होती है। जिस व्यवस्था को मैंने कहा इसके लिए मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानता सारी व्यवस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। आसाम की समस्या है, यह आसाम की समस्या क्यों पैदा हुई है? इस पर कोई नहीं सोचेगा कि नागालैंड की समस्या क्यों शुरू हुई? मनीपुर की समस्या आज क्यों हो गई। इन सब चीजों पर बहुत गम्भीरता से जाओगे अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करोगे तब तक इस प्रस्ताव का मंतव्य होगा कि आज कुमारी सरोज खापर्डे ने अपने इस प्रस्ताव को मूव किया था तब कहा था उस वक्त कहा था अगर इससे अलग हट कर के सही माने में यह संकट जो देश के सामने है, टूट की स्थिति में आ गया है, मनुष्य-मनुष्य का दुश्मन हो गया है और एक सूबा दूसरे सूबे को दुश्मनी की निगाह से देखता है। आज बंगाल का आदमी आसाम की धरती पर परदेसी है। एक मलयाली बम्बई की धरती पर परदेशी है, एक तेलगु जानने वाला आदमी कर्नाटक में जाकर परदेशी है... (**व्यवधान**) आप तो शादी वादी करके बस गये हैं, वह बात मैं नहीं कह रहा हूं... (**व्यवधान**) लेकिन कन्नड़चरबरी का क्या है... (**समय** की घंटी) हो सकता है मुझे इतनी बुद्धि नहीं, मैं समझ सकता हूं लेकिन मैं जिस चीज को इंगित कर रहा हूं उसको सोचने की कोशिश कीजिए। एक तरफ हम बात करते हैं, समान एकता की, सम्पूर्ण एकता अखण्डता की, लेकिन कर्म हमारा रोज का ऐसा होता है, राज का, समाज का जिससे बराबरी, गैर-बराबरी और अखण्डता दूर होती जा रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में जो भी आर्थिक निर्माण हुआ वह किन इलाकों में हुआ, वही इलाके हैं जो अंग्रेजों ने बनाये हैं, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। लेकिन हिन्दुस्तान का दिल जहां उसके अधिकांश लोग रहते हैं अगर उन पर आबादी के हिसाब से खर्च होता तो यह स्थिति न होती। बाढ़ और तबाही किस पर आती है। अगर मान लीजिए कल कहीं बाढ़ और तबाही आ गयी, जो लगातार बढ़ रही है और कल लोग इस बात को तय कर लें और कल खुदा-न-खास्ता करोड़ दो करोड़ आदमियों में चेतना आ जाय और ये फैसला कर लें क्योंकि हम जिस बाढ़ पर सदन में बैठकर बहस करते हैं, कुछ नहीं हो पाता--कि हम संसद को घेर लेंगे और इस संसद को घेरकर एक भी आदमी को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक ये फैसला नहीं कर लें, जब तक संसद यह प्रस्ताव पास नहीं करती, यह कानून नहीं बनाती कि बाढ़ और सूखे से जो भी नुकसान होगा जान माल का उसकी हर भरपाई आपको करनी होगी। तब आप क्या करेंगे। तब प्रजातंत्र होगा। क्या भीड़ का मुकाबला आप गोली से करेंगे। इस वास्ते मैंने कहा यह समान चीज है। दूसरी तरफ इसको भी क्यों नहीं देखते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह की व्यवस्था चली है? जितने कल कारखाने वाले हैं वे क्या बनाते हैं, वे किन चीजों के लिए हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। आज खास करके हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में खपत की आधुनिकता का सिद्धांत जितनी तेजी से जोर पकड़ रहा है आज पश्चिम में वह उतनी तेजी से नहीं है। हर आदमी ने अपनी हैसियत का पैमाना अलग बना रखा है। हर आम आदमी की सुख सुविधा को समझने का ख्याल आज किसी को नहीं है। आम आदमी के काम में आने

वाली चोजों के कारखाने कितने हैं ? कितना विकेन्द्रीकरण है । स्वाभाविक है कि अगर हिन्दुस्तान में 40 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा के नीचे हैं और सरकार के लिहाज से सरकारी दफ्तरों में दो ढाई करोड़ लोग बेकारों की लिस्ट में रहेंगे तो क्या आप समझते हैं कि वे इस देश की धरती से मुहब्बत करेंगे । वे कैसे भी होगा अपने स्वार्थ के लिए करेंगे । तो जहां से मैंने बहस शुरू की थी मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य की उत्पत्ति से उसके मन में सम्पत्ति की कल्पना आई और सम्पत्ति का ही अर्जन उसकी सफलता की कुंजी मानी गयी है । सेवा कुंजी नहीं है, सम्पत्ति कुंजी है । किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किसी राजनीतिक का मूल्यांकन आप इस वास्ते कर रहे हैं कि कौन कितना चतुर है और कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है। सेवा उसकी नहीं देखते हैं तो फिर स्वाभाविक है... (**समय की घंटी**) आखिर में मैं एक चीज कह कर खत्म करता हूं। जब मैं समानता और बराबरी की बात करता हूं और उस पर कल्पना की बात करता हूं तो एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान शायद दुनियां का पुरातन जमाने का सबसे बड़ा देश था जिसने नर नारी की समानता कहीं न कहीं कबूल की थी । आज वह समाज में बिल्कुल टूट रही है । उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में दो तरह के इंसान आपको मिलेंगे इंसान से मेरा मतलब मनुष्य है । एक तो वह जो औरत को सिर पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे या दूसरे ऐसे लोग होंगे जो नारियों को पैर की जूती समझते हैं । क्यों समाज बनेगा ? क्यों नहीं खोजेगा । मैं उन आदमियों में से हूं जो अपने सभी साथियों को चाहता हैं। मैं न नारी को सिर पर चढ़ाना चाहता हूं और न उसे पैर की जूती बनाना चाहता हूं मैं तो नारी को बगल में लेकर चलने का हामी हूं। और जब बगल में लेकर चलने का हामी हूं... (**व्यवधान**) आपको भी लगता है जब मैं नारी...

(**व्यवधान**)

श्रीमती सरोज खापर्डे : आपकी असलियत का आज मुझे पता चला । हमें नहीं मालूम था आप इतने रंगीन हो सकते हैं... (**व्यवधान**)

श्री लाडली मोहन निगम : अब देखिए, आप लोगों ने अपनी बात कह दी । जब मैं बगल में ले चलने की बात कहता हूं तो मैं कल्पना कर लेता हूं कि नारी मेरे कन्धे से ऊपर नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों के समान अधिकार हैं समाज के विकास में, दोनों का समान स्थान है समाज में, जिस तरह समाज की दो धुरी और पहिए हैं उसी तरह ये भी विकास की दो धुरी हैं । अगर इन को अवसर के स्थान के दूर रखोगे तो हिन्दुस्तान के करोड़ों पिछड़ों को दूर रखोगे ।

आखीर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने जब समानता की बात की, आज कभी-कभी मेरे दिमाग में एक बात आती है कि क्या वजह है कि हमारा बदकिस्मत देश है जहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, जहां इस तरह की चीजें रोज चला करती हैं, तब मुझे एक ही बात समझ में आई । क्या वजह है कि दुनियां का सब से पुरातन देश---एक प्रश्न मैं आप के सामने रख रहा हूं और सदन से चाहूंगा कि इस पर बहुत गम्भीरता से सोचे---हजार, डेढ़ हजार, दो हजार वर्षों में सात मर्तबा गुलाम हुआ ? जो हिन्दू धर्म के ठेकेदार हों वे इस का जवाब दें । जो इस्लाम के परचम की जवाबदारी करते हैं वे इस का जवाब दें---मैं किसी जाति या धर्म की अवमानना के भाव से नहीं कह रहा हूं---मैं यही प्रश्न हिन्दुस्तान के मुसलमानों से पूछता हूं कि क्या वजह है कि 9 करोड़ के अरब देश और 30-40 लाख वाला तुम्हारा यहूदी देश जब चाहता है हल्का

[श्री लाडली मोहन निगम]

कर देता है, लम्बा मार देता है, तुम कुछ कर नहीं पाते ? उस का कारण है । मुसलमान दुनिया में दो नम्बर की आबादी वाले होते हुए भी दुनिया के मुकाबले खड़े नहीं हो सकते क्यों कि उन की आधी आबादी को लकवा मार गया है, नारी का कई स्थान ही नहीं है वहां । इस तरह, सरोज जी, हिन्दू तो और भी गिरा हुआ है । इसकी आधी आबादी तो क्या--- औरतें बेचारी बन्द हैं, हरिजनों की क्या हालत है । (व्यवधान) मैं एक ही बात कह रहा हूं कि समानता, बराबरी नहीं है ।

डा. रफीक जकरोया (महाराष्ट्र) : आप वाइस चेयरमेन हो कर भी उस तरफ देख रहे हैं ।

श्री लाडली मोहन निगम : जब से आप आ गए हैं, मैं आप की तरफ हो देख रहा हूं । मैं इजराइल का हिमायती नहीं हूं । मेरा दुर्भाग्य है कि हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं । मैं यह जानता हूं कि दुनिया में सिर्फ दो बड़ी ताकतें हैं, बाकी दुनिया के मुल्क सब कुत्ते हैं, उन के इशारों पर भोंका करते हैं, आप कोई बड़े टीपूचन्द नहीं हैं, अगर दुनिया की ताकतें हट जायें तो हमारी पाकिस्तान की लड़ाई सात रोज से ज्यादा टिक नहीं सकती, न किसी का दामन जा कर पकड़ना पड़ेगा । मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं । आप मेरी भावना को समझने की कोशिश करिए । जिस समाज के 80 प्रतिशत भाग को लकवा लगा है वह समाज उन्नति करेगा ? वह समाज उन्नति नहीं करेगा तो जो आप का यह मन्सूबा है यह हमेशा चलता रहेगा । इस लिए मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश से खूनखराबा हटे, अखंडता नष्ट करने वाली जो ताकतें हैं, जो विघटनकारी तत्व हैं वे टूटें तो इसका इलाज यही हो सकता है । आज 30-35 वर्ष में जो हमने मनुष्य-मनुष्य के बीच खाई पैदा की, नर-नारी में असमानता पैदा, एक और दूसरे राज्य के बीच आर्थिक दूरियां पैदा कीं उसको दूर करने के लिए इस संकल्प को आप लेते हैं और अगर आप के संकल्प का यह मंशा है तो मैं इस का एहतराम करता हूं, इस का समर्थन करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद ।

[The Vice-Chairman (Dr. Raflc Zakaria), in the Chair]

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I wholeheartedly support the Resolution which has been moved by our esteemed colleague, Miss Saroj Khaparde. But my only complaint is this. I am really intrigued. After all, why has it fallen on her shoulders to initiate this Resolution when she belongs to a party which is running this Government?

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh); You also support it.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: This is the Government which is at the same time working for and against national integration.

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: You don't say like thia. This is my Resolution,

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I am repeating it. This Government is at the same time[1] working for and against national integration. I will be able to establish it. Kindly have patience and listen to me. I am saying BO because of certain very valid reasons. First of all, you find out the parties and forces with which this ruling party entered into electoral alliance and received support in January 1980 elections. Which were the parties and forces whose support you have taken directly or indirectly recently in Kerala Assembly election? Find this out and then you will be able to follow what I am saying. This will show how consciously or unconsciously you are working against national integration. Whether it is Shiv Sena in Maharashtra, RSS in Keraia, Santhalig in tribal areas and Sant Bhindranwala people, who are talking of Khalistan, they were all actively supporting Congress(I) in Congres[3] parliamentary elections. Still you say

that you are not working against national integration. Then our friend spoke about secularism. Where from will secularism come when the heads of the State and the heads of the Government demonstratively visit re ligious places? A lot of publicity-through radio and other media is there. An appeal is made to the Hindu mind. It does not end here. The trantriks, the brahmacharis; the jyotish aeharyas, all are getting sup. port from the Congress (I) party, from the ruling party. This Govern ment is supporting them,. By doing this what kind of forces are you goihg to create? Still Miss Saroj Khaparde will say that I am saying a wrong thing. *(.Interruptions).* I know you are [a] well.wisher of the ruling party but you should not support your party blindly. What your party or your Government is doiag, you should not support it blind fy. You must distin guish between the wrong and the right things being done and you must stand in protest against those wrong things being done. Then they are talking about Anandpur Sahibji*** (Interruptions). You are appealing to whom? I am only saying what is wrong. (Interruptions). Mr. Shan karanand, *** I have written a letter to the_____

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): The **♦ This should not be allowed,

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I am perfectly Justified., it ia a State action, Mr. Ramakrishnan **" I have written to him. He has not even acknowledged. He says that he is a follower of Jawaharlal Nehru.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: This should not be allowed. *(Interruptions) .*

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I am just giving an example. Jawahar-lal Nehru never visited any religious place demonstratively. On the one hand they are talking...,

SHRIMATI USHA MALHOTRA: This should not be allowed. *(Inter* ruptions).*

5 P.M.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: They are talkisg and talking, only lecturing and introducing Resolu. tions.. .

THE VICE-CHAIRMAN (DR RAFIQ ZAKARIA): I will examine the records and dp the needful.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I am entirely in your hands, Sir. They will only go on lecturing, go on introducing Resolutions, Thereafter they will still say: "We are working for national integration". It is only the present Government which alone te responsible for disintegration of thia country and unless this Government *h* removed, there is no question of anything happening so far as national integration is concerned, because even if we pass this Resolution, if thia Government is here, then in order to retain itself in power, this Government will do everything which will disintegrate the country and they will never work for the integration of thia country.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Thank you, Mr. Bhattacharya. I think we go now to the Half-an-Hour Discussion by Mr. A. G. Kulkarni.

SOME HON. MEMBERS: What happens to the Resolution?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The Resolution lapses.

SHRI ARVIND GANESH KUL. KARNI; Mr. Vice-Chairman, Sir.. .

SHRIMATI SAROJ KHAFARDE: The Minister of State for Home is here.

* Expunged a3 ordered by the Chair.

मैंने इतना महत्वपूर्ण रेंजोल्यूशन दिया है। उसके सम्बन्ध में मैं चाहती थी कि मंत्री जो कुछ आश्वासन दें। इतना इंपार्टेंट रेंजोल्यूशन आने के बाद और इतने सारे स्पीकर्स के बोलने का क्या लाभ होगा यदि मंत्री जी इस पर कुछ न कहें तो।

SHRIMATI MONIKA. DAS (Kama, taka): We do not mind if the Resolution lapses. But the Minister should give some reply.

SHRIMATl SAROJ KHAPARDE: At least he should give Borne assur, ance.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Is rhe Minister inclined to say something in the matter?

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: I would be grateful if the Mmister repliesi,

THE MINISTER OF STATE iN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): But, Sir, the ruling of the Chair is there.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): That is all right.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH; The ruling of the Chair ig there, I have, obeyed the Chair. I have nothing more to say.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The ruling of the Chair can be modified if the Minis, ter.. .

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I have nothing to say.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): That is all right.

SHRl 6. C. BHATTACHARYA: Miss Khaparde, you will not get any answer to your Resolution.

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: That ^ what I am requesting for. At least he should give some assurance.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): In fact, I have gone to the extent of saying that I will even modify my ruling in case the Minister wag inclined to say some, thing. But he says, he has nothing to add. So I have no choice but to caL upon Mr. Kulkarni. *(Interruptons)*

SHRl GHULAM RASOOL MATTO; Sir, I am on a point of 6rder. If other speakers have not been given a chance to speak on the subject even though they were listed there, it is not pro" per for the Minister to reply. The ruling that you have given is hundred per cent correct and that should stand Unless we all are allowed to speak— we will sit upto midnight, We do not mind—after the Half.an-Hour Discussion when all others who are listed have spoken, in support of it or otherwise, then alone the Minister can reply. If it is not to be so, then your ruling Should stand.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): You see, the position is that as far as Non-offlcial Business is concerned, a particular fixed time is given. Therefore, that fixed time is over. But since the mover of the Resolution made a re. quest that the Minister of State for Home is present, and on an important matter like this, if he would say something in terms of any assurance and other things, that would be better. I thought for a minute or two I can request Mr. Kulkarni to wait. But since he says that he hag nothing tO say, I do not think any useful purpose will now be served by our prolonging this kind of a discussion. I would, therefore, request Mr Kulkarni now to raise the Half-an-Hour Discussion.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Re. points arising out of answer to Unstarred Question No. 72 given on 4th October, 1982, regarding import of power equipments for Chandrapur and Anpara Super Thermal Power

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission